

समाचार पचीसा

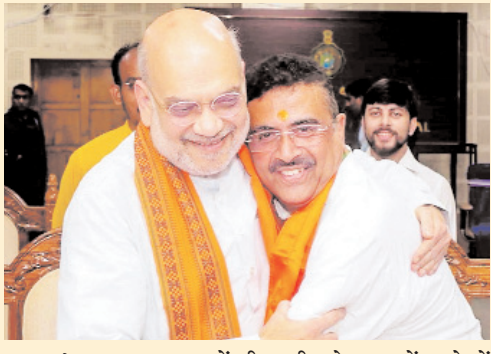
राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8> अबूझमाड़ के कुतुल पहुंचे...



बंगाल सीएम के नाम का ऐलान आज

कोलकाता। बीजेपी जल्द ही पश्चिम बंगाल के सीएम के नाम का ऐलान कर सकती है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि शुक्रवार को इस संबंध में पार्टी एक बड़ी बैठक करने जा रही है। ऐसी संभावनाएं हैं कि इसके बाद विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा हो सकती है। बीजेपी ने बंगाल का पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नियुक्त किया है।



मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को बीजेपी के विधायकों की बैठक कोलकाता में होने जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि इस बैठक में शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल के नेता का तौर पर चुना जाएगा। बीजेपी के प्रदेश प्रमुख शक्ति भट्टाचार्य अधिकारी के नाम का प्रस्ताव रखेंगे और शाह उनके नाम की घोषणा करेंगे। बीजेपी ने अभी तक औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन गृह मंत्री शाह सहित वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान संकेत दिया था कि अमला सीएम पश्चिम बंगाल से ही होगा।

बता दें साल 2021 में शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी से राहें अलग कर ली थीं। इतना ही नहीं, वह उनके खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव में भी उतरे। और सीएम ममता को हार का सामना करना पड़ा था। माना जाता है कि

साल 2011 में टीएमसी को सत्ता में लाने में नंदीग्राम की भूमिका बड़ी रही थी। इसके बाद 2026 में भी बीजेपी ने शुभेंद्र अधिकारी को ममता के सामने उतारा, लेकिन मैदान बदलकर सीएम के गढ़ भवानीपुर पहुंच गया। यहां भी नतीजा वही हुआ और शुभेंद्र ने करीब 15 हजार मतों के अंतर से विजय हासिल की।

जीत के बाद शुभेंद्र अधिकारी ने राज्य की जनता को भारी समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि नई सरकार जनसेवा और समावेशी विकास को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक विकसित, समृद्ध और सुरक्षित पश्चिम बंगाल के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। सभी के साथ मिलकर, हम एक स्वस्थ, सुंदर और विकसित राज्य का निर्माण करेंगे। राज्य की जनता की सेवा करना नई सरकार का प्राथमिक लक्ष्य होगा।

इस्तीफे से फिर किया इनकार

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पद छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगी, अगर किसी को हटाना है तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी ने पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में यह बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं था और उनके कई उम्मीदवारों को जबरन हराया गया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 1500 से अधिक टीएमसी



कार्यालयों पर कब्जा कर लिया गया ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे चुनाव नहीं, बल्कि अत्याचार बताया। उन्होंने राज्य पुलिस, केंद्रीय बलों और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि इन संस्थाओं ने निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल चुनाव के बाद दृष्टिगत गठबंधन में एकजुटता और मजबूत हुई है। ममता ने अपने समर्थकों से अपील की कि वे संघर्ष जारी रखें और विधानसभा के पहले दिन काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कराएं। ममता बनर्जी ने अपने भाषण में कहा कि वह इस हार को अंतिम नहीं मानतीं और आगे भी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेंगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पार्टी के भीतर जो लोग विश्वासघात करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

तमिलनाडु में सरकार गठन में फंसा पेच?

नई दिल्ली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद तमिलनाडु वेदी कड़गम (टीवीके) ने राज्य में सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। टीवीके प्रमुख विजय ने बुधवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर से राजभवन में मुलाकात की। उन्होंने राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। सूत्रों के अनुसार, विजय ने राज्यपाल को विधायकों के समर्थन का जो पत्र सौंपा है, उसमें 112 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, राज्यपाल अभी तक टीवीके के दावे से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि पार्टी के पास बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं।



तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है। इस चुनाव में विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी ने टीवीके को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस के पास विधानसभा में 5 सीटें हैं। कांग्रेस के समर्थन के बाद विजय की पार्टी टीवीके के गठबंधन की संख्या 234 सदस्यीय विधानसभा में 113 तक पहुंच गई है। क्योंकि विजय ने दो सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर ही जीत हासिल की थी। ऐसे में अब उनको एक सीट छोड़नी होगी। इसके बाद टीवीके का आंकड़ा 112 विधायकों का ही रह जाता है। अब 118 के बहुमत के आंकड़े को पार करने के लिए पार्टी को कम से कम छह और विधायकों की आवश्यकता होगी। इसे लेकर विजय ने बीसीके, सीपीआई और सीपीएम जैसे दलों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव में डीएमके को 59 और एआईएडीएमके को 47 सीटें मिली हैं। अन्य दलों में पीएमके को 4 और

आईयूएमएल को 2 सीटें मिली हैं। सीपीआई, बीसीके और सीपीआईएम को भी 2-2 सीटों पर जीत मिली है। भाजपा, डीएमडीके और एएमएमके के खते में 1-1 सीट आई है। टीवीके सबसे ज्यादा 108 सीटें मिली हैं।

राज्यपाल से मुलाकात के बाद अब सरकार गठन की औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक, विजय 7 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। विजय के राजनीति में आने और पहली बार में ही इतनी बड़ी जीत दर्ज करने से राज्य के सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। कांग्रेस ने लंबे समय से सहयोगी रही डीएमके से नाता तोड़कर सरकार बनाने के लिए विजय की टीवीके को अपना समर्थन देने की घोषणा की। कांग्रेस ने कहा कि टीवीके प्रमुख विजय के समर्थन मांगने के बाद यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए पार्टी मुख्यालय सत्यमूर्ति भवन में पटाखे फोड़े।



रायपुर। नारायणपुर के शिक्षा जगत के लिए आज का दिन उत्साह भरा रहा। प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने नारायणपुर जिले के उन प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया, जिन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया है।

वंदे मातरम के अपमान पर होगी जेल

■ मोदी कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी, राष्ट्रगान के बराबर मिला दर्जा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस बदलाव के बाद अब वंदे मातरम के गायन में बाधा डालना या उसका अपमान करना एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। अब राष्ट्रीय गीत को भी वही कानूनी संरक्षण

प्राप्त होगा जो राष्ट्रगान जन गण मन को मिला हुआ है।

तीन साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान

मौजूदा कानून के तहत अभी तक केवल राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के अपमान पर ही सजा का प्रावधान था। झंडे को जलाने, विकृत करने या राष्ट्रगान को जानबूझकर बाधा डालने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है। अब नए संशोधन के बाद, वंदे मातरम के साथ भी ऐसी ही हरकत करने पर समान सजा का सामना करना पड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार, संसद की मुहर लगते ही यह नया कानून प्रभावी हो जाएगा।

सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा की ओर कदम

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए इसे करोड़ों भारतीयों के लिए गर्व का क्षण बताया। ठाकुर ने कहा कि वह लंबे समय से वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा देने की मांग कर रहे थे। उन्होंने बजट सत्र के दौरान लोकसभा में नियम 377 के तहत यह मुद्दा उठाया था। उनका मानना है कि इस कदम से हमारी सांस्कृतिक विरासत पर होने वाले जानबूझकर हमलों को रोका जा सकेगा।

गायन के लिए नया प्रोटोकॉल तय

इसी साल जनवरी में गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम के लिए एक विस्तृत प्रोटोकॉल भी जारी किया था। इसके अनुसार, आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम की छह पंक्तियां गाई जाएंगी, जिनकी अवधि तीन मिनट 10 सेकंड होगी। महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी समारोह में जहां राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों होने हों, वहां वंदे मातरम पहले गाया जाएगा। राष्ट्रपति के आगमन और ध्वजारोहण जैसे मौकों पर वंदे मातरम के समय सभी को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य होगा।

ईसीआईनेट ऐप से चुनाव प्रक्रिया हुई तेज: आयोग

नयी दिल्ली। चुनाव आयोग ने कहा है कि हाल में हुए विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के दौरान आयोग के आधिकारिक ऐप ईसीआईनेट सूचना के त्वरित संप्रेषण, चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के साथ ही सुदृढ़ साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ है। आयोग के एक प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि उसके सशक्त सूचना प्रौद्योगिकी मंच ईसीआईनेट ने चुनावी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने के साथ ही तात्कालिक अनुश्रवण, शोध प्रतिवेदन तथा पारदर्शिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका कहना था कि इस साल जनवरी में इस ऐप के औपचारिक शुभारंभ के बाद इसके उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और 10 करोड़ से अधिक बार इसे डाउनलोड किया जा चुका है। इससे पूर्व इसका बीटा संस्करण नवंबर में बिहार चुनावों में प्रयुक्त किया गया था। प्रवक्ता के अनुसार हाल ने हुए मतदान के दिनों में, 23 और 29 अप्रैल को ईसीआईनेट पर 98.3 करोड़ से अधिक हिट्स दर्ज की गईं, जबकि महागणना के दिन चार मई को औसतन प्रति मिनट तीन करोड़ हिट्स दर्ज हुईं।

किसी की पुश्तैनी संपत्ति नहीं भ्रम में न रहे ममता: दिलीप

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के सीएम पद न छोड़ने पर कहा कि राजनीतिक पद केवल सीमित समय के लिए होता है। इसलिए ममता बनर्जी किसी भ्रम में न रहें। घोष ने बुधवार सुबह कहा कि एक दिन हर किसी को यह दुनिया छोड़कर जाना ही है। राजनीतिक पद केवल सीमित समय के लिए होता है। यह गद्दी तो दो दिन की है, इसलिए किसी भ्रम में न रहें। यह किसी की पुश्तैनी संपत्ति नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता ने 15 साल का समय दिया था। उन्होंने सिवाय हिंसा और भ्रष्टाचार के, बंगाल में कोई काम नहीं किया। टीएमसी के कार्यकाल में लोगों का जीना मुश्किल हो चुका था जिस डॉक्टर बेटी का रेप-मर्डर हुआ। उसे न्याय नहीं मिला, बल्कि पीड़िता की मां का टीएमसी के नेताओं ने अपमान किया। इन सभी बातों को जनता भूली नहीं है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, आज दुनिया को इससे मतलब नहीं है।

भारत खुशकिस्मत है जिसे नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला: ट्रंप

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के सियासी अखाड़े में इस बार ऐसा उलटफेर हुआ है जिसकी गूंज सात समंदर पार अमेरिका तक जा पहुंची। बंगाल में पहली बार बीजेपी की प्रचंड जीत और ममता बनर्जी के 'किले' के ढहने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को खास अंदाज में बधाई दी। ट्रंप ने इस जीत को 'ऐतिहासिक और निर्णायक' बताया है। बंगाल चुनाव के नतीजों ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि जिस राज्य में दशकों तक टीएमसी और वामपंथियों का बोलबाला था, वहां अब बीजेपी का परचम लहरा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई के मुताबिक ट्रंप ने पीएम मोदी को इस धमाकेदार जीत के लिए खुद मैसेज भेजकर बधाई दी है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि भारत खुशकिस्मत है जिसे मोदी जैसे पीएम मिले हैं। ट्रंप का ये खास संदेश साफ बताता है कि बंगाल की इस जीत की गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है।

चुनाव आयुक्त कानून पर केंद्र की अर्जी खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टालने से साफ इनकार कर दिया है। बुधवार को शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की उस दलील को ठुकरा दिया, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अन्य व्यस्तताओं का हवाला देकर समय मांगा था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि यह मामला देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह फिलहाल सबरीमाला मंदिर से जुड़े नौ जजों की पीठ के सामने व्यस्त हैं। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा, यह मामला किसी भी अन्य विषय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने केंद्र को निर्देश दिया कि उनके सहयोगी वकील आज नोट्स लें, लेकिन सुनवाई नहीं रकेगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को गुरुवार तक अपनी बहस पूरी करने का आदेश दिया है। इससे पहले 20 मार्च को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया था।

बंगाल नतीजों को अविश्वसनीय बताया तेजस्वी यादव ने

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए परिणाम को अप्रत्याशित बताया और साथ ही अपनी पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा कि हमें बंगाल में इस तरह के नतीजों की उम्मीद नहीं थी। लेकिन चूंकि भाजपा सत्ता में है, इसलिए पूरी व्यवस्था और तंत्र उनके हाथों में है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी विचारधारा यह है कि हार-जीत ज्यादा मायने नहीं रखती; कई चुनाव होंगे, आते रहेंगे, लेकिन हम अपनी विचारधारा, अपनी नीतियों और सिद्धांतों के लिए लड़ेंगे और भाजपा-आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने बिहार में मंत्रिमंडल गठन में भी नई गति देनी की भी आलोचना की और सरकार की स्थिरता और विकास पर इसके प्रभाव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर 7 महीनों में सरकार नहीं बनी, तो क्या बिहार को फायदा होगा? मंत्रिमंडल अभी तक नहीं बना है और इन 6 महीनों में हमने दो मुख्यमंत्री देख लिए हैं।

भारत और वियतनाम ने अपने संबंधों को स्तर तक पहुंचाने का लिया ऐतिहासिक निर्णय

वियतनाम की चम्पा सभ्यता की पाण्डुलिपि होगी डिजिटलाइज

नई दिल्ली। भारत और वियतनाम ने अपने संबंधों को नई ऊंचाई देते हुए उन्हें एंहांसड कॉम्प्रेहेंसिव स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप के स्तर तक पहुंचाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में हुई बातों के बाद दोनों देशों ने रक्षा, आर्थिक सहयोग, डिजिटल भुगतान, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और सामरिक साझेदारी को और गहरा करने पर सहमति बनाई। यह यात्रा राष्ट्रपति तो लाम की पद संभालने के बाद पहली राजकीय भारत यात्रा थी, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को नया रणनीतिक आयाम दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त प्रेस

वार्ता में कहा कि वियतनाम भारत की एक ईस्ट नीति और विजय महासागर का प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर साझा दृष्टिकोण है और वे कानून आधारित व्यवस्था, शांति, स्थिरता तथा क्षेत्रीय समृद्धि के लिए मिलकर कार्य करते रहेंगे। यह बयान ऐसे समय आया है जब दक्षिण चीन सागर और व्यापक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक प्रतिस्पर्धा लगातार तेज हो रही है। माना जा रहा है कि वार्ता के दौरान चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता और समुद्री विस्तारवाद पर भी गंभीर चर्चा हुई। हम आपको बता दें कि भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग

लगातार मजबूत हो रहा है। पिछले वर्ष दोनों देशों ने पनडुब्बी खोज, बचाव और सहायता तंत्र विकसित करने का समझौता किया था। इसके साथ ही रक्षा उद्योग सहयोग को बढ़ाने के लिए भी सहमति बनी थी। अब नई रणनीतिक साझेदारी के तहत रक्षा, समुद्री सुरक्षा और सैन्य प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सहयोग और व्यापक होगा। इसका सामरिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि वियतनाम दक्षिण चीन सागर में चीन के दबाव का सामना कर रहा है, जबकि भारत हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में संतुलित शक्ति



व्यवस्था बनाए रखने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में दोनों देशों का सहयोग क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आर्थिक मोर्चे पर भी दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पिछले एक दशक में भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर 16 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। अब इसे वर्ष

2030 तक 25 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। दोनों देशों ने दवाओं, कृषि उत्पादों, मत्स्य और पशु उत्पादों के व्यापार को आसान बनाने के लिए कई समझौते किए। भारत के अंगूर और अनार अब वियतनाम भेजे जाएंगे, जबकि वियतनाम का डूरियन और पोमेलो भारत पहुंचेगा। डिजिटल और वित्तीय सहयोग के अंतर्गत वियतनाम को सुरक्षित और विविध बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को भी नई गति देने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम में भारतीय बौद्ध अवशेषों के दर्शन डेढ़ करोड़ से अधिक लोगों ने किए।

वियतनाम के केंद्रीय बैंक के बीच समझौता हुआ। इससे दोनों देशों के व्यापारियों, पर्यटकों और निवेशकों को सीमा पार भुगतान में बड़ी सुविधा मिलेगी। यह पहले भारत की डिजिटल भुगतान क्षमता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने के साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया में उसकी तकनीकी उपस्थिति को भी मजबूत करेगी। दोनों देशों के बीच कुल 13 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें दुर्लभ खनिज तत्वों संपर्क बढ़ाने की दिशा में भी बड़ा कदम डिजिटल तकनीक, पर्यटन, औषधि नियमन, शिक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और शहरी प्रबंधन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। विशेष रूप से दुर्लभ खनिज

तत्वों पर सहयोग का समझौता सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज के दौर में दुर्लभ खनिज सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण, बैटरी और उच्च तकनीकी उद्योगों की रीढ़ बन चुके हैं। चीन इन संसाधनों पर लंबे समय से प्रभाव रखता है। ऐसे में भारत और वियतनाम का यह सहयोग आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित और विविध बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को भी नई गति देने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम में भारतीय बौद्ध अवशेषों के दर्शन डेढ़ करोड़ से अधिक लोगों ने किए।

जनता की संप्रभुता का ममता को सम्मान करना चाहिए

संजय गोस्वामी

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो चुनाव नहीं हारी हैं इसलिए इस्तीफा नहीं देंगी ऐे कहना ठीक नहीं है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मिली हार ने ममता बनर्जी के आगे की राजनीतिक सफर को काफी मुश्किलों भरा बना दिया है। ममता बनर्जी ने सिर्फ़ सत्ता ही नहीं गंवायी बल्कि अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर को भी हार गई अब ऐे कहना कार्डटिंग में धांधली हुई है इसलिए इस्तीफा नहीं देंगी गलत है ऐे लोकतांत्रिक देश है इसमें जनता का निर्णय सर्वोपरि है। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद हिंसा होना बिल्कुल गलत है ऐे राज्य सरकार की जिम्मेदारी है अतः ऐसी घटना को शक्ति से पालन करना चाहिए और कोई भी पार्टी का हो दंगा करने पर उचित कार्यवाही करना चाहिए इस चुनाव में कांग्रेस और टीएमसी में वोट कटा है रही सही कसर लेफ्ट और एआईएमआईएम ने भी वोट काटा है इस चुनाव में सबसे ज्यादा खुश कांग्रेस हुई होगी क्योंकि विपक्ष में ममता दीदी का बढ़ता कद को देखकर कांग्रेस चिंता में थी अब विपक्ष में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनी है भले ही सीटों की संख्या कम हो लेकिन अधिक मात्रा में अल्पसंख्याक का वोट काटा है लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही सर्वोपरि है और उसका सम्मान करना चाहिए और हार को स्वीकार कर विपक्ष में ही सही जनता के निर्णय को सम्मान करना चाहिए लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें देश की सत्ता जनता के हाथों में होती है। इसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वे प्रतिनिधि जनता के हित में शासन चलाते हैं। सरल परिभाषा : लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता को अपने शासकों को चुनने का अधिकार होता है। सत्ता का अंतिम स्रोत जनता होती है। प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित अंतराल पर होता है। समानता: सभी नागरिकों को कानून के सामने समान अधिकार प्राप्त होते हैं। स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, और संगठन की स्वतंत्रता होती है। कानून का शासन: सभी नागरिक और शासक कानून के अधीन होते हैं। बहुमत का शासन, अल्पमत का सम्मान करना ही लोकतंत्र की ताकत है जिसमें निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन अल्पमत के अधिकारों की रक्षा की जाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी शामिल है जो न्यायालय स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। जहाँ तक उत्तरदायित्व और पारदर्शिता का सवाल है वो चुनाव से पहले होता है जिसमें शासक जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और शासन में पारदर्शिता होती है। यानी व्यावहारिक अर्थ जनता की संप्रभुता की रक्षा करना है: नागरिक ही सरकार को बदल देती हैं। चुनाव हर 5 साल में चुनाव होते हैं तो अगली बार के लिए कहाँ कहाँ गलती हुई इसपर ध्यान देकर विपक्ष में भी रहकर जनता की सेवा करने से पुन: चुनाव में जीत हो सकती है। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई भी अपनी राय रख सकता है, संगठन बना सकता है। कानून का शासन: कोई भी कानून से ऊपर नहीं। बहुमत का शासन, अल्पमत का सम्मान: बहुमत से सरकार बनती है, लेकिन अल्पमत की बात भी सुनी जाती है। उत्तरदायित्व और पारदर्शिता: सरकार को अपने कार्यों का हिसाब देना पड़ता है लोकतंत्र की न्यूनतम विशेषताएँ हैं: जनता की संप्रभुता, समानता, स्वतंत्रता, कानून का शासन, और उत्तरदायित्व। इनसे ही किसी शासन को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है।अगर लागता है की कार्डटिंग में कुछ गड़बड़ी हुई है तो अदालत है जिसमें न्यायपालिका के सामने अपनी बात रखने का अधिकार है जो अदालतें सरकार के दबाव में नहीं होतीं। इसलिए अब चुनाव परिणाम आने के बाद कुछ नहीं हो सकता है।

पुराण दिग्दर्शन

सन्देहाभासनिकारणाध्याय: (नौवां अध्याय)

(गतांक जे आगे...)

(च) बहत् ही भारद्वाज है ।

(छ) दशमयुग सृष्टि के आरम्भ से दो चतुर्गुी व्यतीत होकर आने वाले चैता में ममता का बेटा दीर्घमता नामक ऋषि मन्त्र-द्रष्टा हुआ ।

पौराणिक स्वरूप

अन्तर्वन्यायं धातृपत्न्यायं मैथुनाय बृहस्पतिः ।

प्रवृत्तो वारितो गर्भं शम्वा चोर्यमवासुजत् ॥३6 ॥

तं त्पकुक्षामां समतां भर्तुं त्यागविशुङ्क्षताम् ।

नामनिर्वचनं तस्य श्लोकमेनं सुरा जगुः ॥३7 ॥

मुहूर्तं भर द्वाजमिमं भर द्वाजं बृहस्पते ! ॥

चांघमाना सुरैरेवं मत्त्वा वितथमात्मजम् ।

यातो यदुकृत्वा पितरौ भरद्वाजस्ततस्त्वयम् ॥ 38 ॥

व्यसुजन्मरुतो विभ्रन्दतोऽयं वितथेऽन्वये । ३9 ॥

(श्रीभद्भाविवत 6 १20)

अर्थात्- गर्भवती भाई की स्त्री के साथ बृहस्पति मैथुन करने के लिये प्रवृत्त हुआ । [गर्भस्थ बालक ने]



निषेध किया अतः उसको अन्ध हो जाने का] शाप देकर [बाहिर ही] वीर्य छोड़ दिया ॥ 33 ॥ पति के त्याग देने के भय से ममता ने उस [प्रस्खलित वीर्य द्वारा उत्पन्न हुये बालक] को छोड़ना चाहा, तब देवताओं ने ममता के प्रति उस [सद्यो-जात शिशु] का नाम निर्वचन-भूत यह श्लोक पढ़ा ॥ 37 ॥ हे मूर्ख ! दो से उत्पन्न होने वाले इस बालक का तू पालन कर ! हे बृहस्पते ! तू भी इस द्वाज दूसरे के क्षेत्राश्रय से अन्य वीर्यजात बालक का भर-पोषण कर । इस तरह परस्पर कहते हुये ममता और बृहस्पति दोनों ही उस बालक को छोड़ कर खिसक गए, इसलिए इसका नाम भारद्वाज ऐसा प्रसिद्ध हुआ ॥३8 ॥ देवताओं के कहने पर भी ममता ने इस बालक को विष्य व्यध्रायः अनावश्यक निरर्थक एव व्यभिचारजात जानकर छोड़ दिया, तब इस अनाथ को मरुत नामक देवताओं ने प्राप्त कर के भरत के वंश में दे दिया ॥ 36 ॥

क्रमशः ...

ज्ञान/मीमांसा

संघ की जमीनी साधना शांति से शक्ति तक

ललित गर्ग

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ऐतिहासिक, अद्भुत, अविस्मरणीय एवं करिश्माई जीत के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (संघ) की बहुत बड़ी भूमिका रही है। निश्चिततौर पर इस शानदार जीत के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह मुख्य भूमिका में हैं। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी की मजबूत चुनौती के सामने भाजपा की जीत के लिए संघ लंबे समय से मेहनत कर रही थी और उसकी वह मेहनत ही जीत का सशक माध्यम बनी है। पश्चिम बंगाल में लगातार चल रही हिन्दू विरोधी गतिविधियों एवं मुसलमानों के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए संघ ने इस चुनाव के मद्देनजर बहुत पहले से ही कमर कस ली थी, संघ ने पश्चिम बंगाल में 1.75 लाख से अधिक छोटी-बड़ी बैठकें आयोजित कों। पिछले 15 सालों में संघ ने पश्चिम बंगाल में तेजी से विस्तार किया है और एक मजबूत 'हिंदू वोट बैंक' तैयार किया है। पश्चिम बंगाल में पिछले 15 वर्षों में संघ की शाखाओं की संख्या 900 से बढ़कर 5,000 तक पहुंच गई है। संघ के स्वयंसेवकों ने पश्चिम बंगाल में घर-घर जाकर 'बंग बचाओ' इस थीम पर 'मतदाता जागरूकता अभियान' चलाया। संघ की माइक्रो प्लांटिंग ने बंगाल में भाजपा को ऐतिहासिक बढ़त दिलाई और सत्ता परिवर्तन का माध्यम बनी। पश्चिम बंगाल चुनाव भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक 'मील का पत्थर' और ऐतिहासिक सफलता साबित हुआ।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि राजनीति केवल बड़े मंचों, विशाल रैलियों और जोरदार नारों से तय नहीं होती। कई बार असली लड़ाई उन स्तरों पर लड़ी जाती है, जहां न कैमरे पहुंचते हैं और न ही जमीनी प्रयास सुर्खियां बनती हैं। इस बार के चुनाव में एक ऐसी ही खामोश रणनीति कारगर साबित हुई है। जहां एक ओर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का आक्रामक चुनाव प्रचार केंद्र में रहा, वहीं दूसरी ओर संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अपेक्षाकृत शांत रहकर 'निःशब्द विप्लव' या 'मूक क्रांति' को अंजाम देते हुए जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने पर ध्यान दिया। बंगाल की अस्मिता, विकास और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों को आधार बनाकर जनजागरण अभियान चलाया गया। इस दौरान महिला, युवा,



प्रबुद्ध वर्ग, किसान, श्रमिक और अनुसूचित जाति-जनजाति समुदायों तक अलग-अलग तरीकों से पहुंचने की कोशिश की गई।

निश्चिततौर पर पश्चिम बंगाल की राजनीति ने वर्ष 2026 में जो ऐतिहासिक करवट ली, वह केवल सत्ता परिवर्तन की घटना नहीं है, बल्कि एक गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक परिवर्तन का संकेत भी है। लंबे समय तक वामपंथी प्रभाव और उसके बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व में आॅल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व रहा, लेकिन इस बार जनमत ने जिस प्रकार से भाजपा के पक्ष मंर निर्णायक रूप से झुकाव दिखाया, उसने स्थापित राजनीतिक धारणाओं को चुनौती दी है। इस परिवर्तन के मूल में जो शक्ति को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी रही है तो वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने एक अदृश्य लेकिन अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाई है। यह विजय केवल चुनावी रणनीतियों का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों से चल रहे संगठनात्मक परिश्रम, वैचारिक विस्तार और समाज के भीतर गहराई तक किए गए संवाद का परिणाम है। पश्चिम बंगाल में संघ का विस्तार किसी तात्कालिक राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं था, बल्कि यह एक दीर्घकालिक सामाजिक दृष्टि का हिस्सा था। पिछले डेढ़ दशक में संघ ने प्रांत में जिस प्रकार अपनी शाखाओं का विस्तार किया और समाज के विभिन्न वर्गों तक अपनी पहुंच बनाई, उसने एक मजबूत वैचारिक आधार तैयार किया। यह कार्य किसी प्रचार की तरह नहीं, बल्कि एक शांत सामाजिक प्रक्रिया एवं क्रांति की तरह हुआ, जिसने धीरे-धीरे जनमानस को प्रभावित किया। यही कारण है कि जब चुनाव का समय आया, तो एक पहले से तैयार मानसिकता भाजपा के पक्ष में खड़ी दिखाई दी।

इस पूरे परिदृश्य में सरसंघचालक मोहन भागवत की रणनीतिक दृष्टि को भी विशेष रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए। उन्होंने बंगाल को केवल एक राजनीतिक इकाई के रूप में नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक भूमि के रूप में देखा,

भारत की अस्मिता के रूप में देखा। जिसकी अपनी विशिष्ट पहचान और परंपराएं हैं। संघ के प्रयासों में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उसने बंगाल की सांस्कृतिक चेतना को समझने और उससे जुड़ने का प्रयास किया। दुर्गा पूजा, काली पूजा और रामनवमी जैसे पर्वों को सामाजिक एकता और सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिससे एक व्यापक सामाजिक जुड़ाव स्थापित हुआ। इस प्रक्रिया में हिंदुत्व को किसी बाहरी विचारधारा के रूप में नहीं, बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक आत्मा के एक स्वाभाविक विस्तार के रूप में प्रस्तुत किया गया। लंबे समय तक यह धारणा बनी रही कि बंगाली अस्मिता और हिंदुत्व परस्पर विरोधी हैं, लेकिन इस चुनाव में यह धारणा काफी हद तक टूटती हुई दिखाई दी। जय श्री राम के साथ जय मां काली और जय मां दुर्गा जैसे नारों का समन्वय केवल राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक संदेश था, जिसने यह स्थापित किया कि क्षेत्रीय पहचान और व्यापक सांस्कृतिक विचारधारा के बीच कोई टकराव नहीं है। इस समन्वय ने मतदाताओं के भीतर एक नई प्रकार की आत्मजागरूकता उत्पन्न की, जहां वे केवल विकास या योजनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी पहचान, सुरक्षा और सांस्कृतिक गौरव के आधार पर भी निर्णय लेने लगे।

चुनाव के दौरान जिस प्रकार से 'अस्तित्व' एवं 'अस्मिता' का विमर्श उभरा, उसने इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को एक नई दिशा दी। संघ और भाजपा ने इसे केवल एक चुनावी मुकाबले के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि एक वैचारिक संघर्ष के रूप में स्थापित किया, जिसमें पहचान और सम्मान के प्रश्न प्रमुख हो गए। आॅल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पर लगाए गए तुष्टिकरण के आरोपों ने इस विमर्श को और तीव्र किया, जिससे मतदाताओं के बीच एक स्पष्ट ध्ववीकरण देखने को मिला। इस पूरे प्रक्रिया में संघ ने जमीनी स्तर पर संवाद स्थापित कर इस विचार को सामाजिक स्वीकृति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संगठनात्मक दृष्टि से भी यह चुनाव एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार मजबूत जमीनी ढांचा चुनावी सफलता का आधार बन सकता है। बूथ स्तर तक सक्रियता, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय, गुटबाजी पर नियंत्रण और नए-पुराने कार्यकर्ताओं का एकीकरण-इन सभी पहलुओं में

विश्व एथलेटिक्स दिवस



सुविधाओं की तरफ बढ़े, हमने बच्चों के भीतर के इस खिलाड़ी को सुरक्षा और पढ़ाई के नाम पर घरों के भीतर कैद कर दिया है । एक दौर था जब गाँव की पगडंडियों पर नंगे पैर दौड़ना या स्कूल के ऊबड़-खाबड़ मैदानों में पसीना बहाना ही दिन की सबसे बड़ी खुशी होती थी। तब न महंगे जूते थे, न कोई खास डाइट और न ही वातानुकूलित जिम। फिर भी शरीर मजबूत रहता था और मन में गजब का उत्साह। आज तकनीक ने हमें सब कुछ दे दिया है, बस वह पसीना बहाने वाला ज़मीन का रिश्ता कहीं पीछे छूट गया है। आज का बच्चा स्कूल की पढ़ाई, भारी-भरकम ट्यूशन और फिर अंतहीन मुकाबलों की ऐसी अदृश्य रेस में दौड़ रहा है, जहाँ वह मानसिक रूप से तो थक जाता है, उसका शरीर सुस्त पड़ा रहता है। जब भी ओलिंपिक जैसे बड़े खेल होते हैं, तो नीरज

संघ की भूमिका महत्वपूर्ण रही। यह केवल एक राजनीतिक दल का प्रयास नहीं था, बल्कि एक व्यापक संगठनात्मक सहयोग का परिणाम था, जिसने भाजपा को एक सशक्त चुनावी शक्ति के रूप में स्थापित किया।

इस जीत में नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह की रणनीतिक क्षमता ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन इन प्रयासों को प्रभावी बनाने के लिए जिस सामाजिक आधार की आवश्यकता थी, वह संघ ने तैयार किया। यही कारण है कि यह जीत केवल शीर्ष नेतृत्व की सफलता नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर किए गए सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। इस चुनाव में बंगाल के मध्यम वर्ग का झुकाव भी एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में सामने आया। यह वर्ग परंपरागत रूप से विचारशील और राजनीतिक रूप से सजग माना जाता है और इसका समर्थन किसी भी राजनीतिक दल के लिए निर्णायक होता है। संघ ने इस वर्ग के बीच संवाद और जागरूकता के माध्यम से एक वैचारिक आधार तैयार किया, जिससे यह वर्ग भाजपा के समर्थन में एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरा। इस पूरे परिवर्तन को जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दृष्टिकोण और उनके सपनों के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। उन्होंने जिस राष्ट्रवादी विचारधारा की नींव रखी थी, उसे आज बंगाल की धरती पर एक नए रूप में साकार होते हुए देखा जा रहा है। यह केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक वैचारिक निरंतरता का प्रतीक भी है। अंततः यह स्पष्ट होता है कि पश्चिम बंगाल 2026 का चुनाव केवल एक चुनावी घटना नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन का प्रतीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस प्रकार से वर्षों तक धैर्य और अनुशासन के साथ समाज के भीतर कार्य किया, वह आज परिणाम के रूप में सामने आया है। यह परिवर्तन यह संकेत देता है कि जब संगठनात्मक शक्ति, वैचारिक स्पष्टता और नेतृत्व की दिशा एक साथ मिलती हैं, तो वे न केवल राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करती हैं, बल्कि समाज की दिशा को भी बदलने की क्षमता रखती हैं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह परिवर्तन किस प्रकार आगे विकसित होता है और क्या यह केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित रहता है या एक स्थायी सामाजिक पुनर्जागरण का आधार बनता है।

पश्चिम बंगाल में अब बदला नहीं बदलाव की राजनीति

कृष्णमुरारी त्रिपाठी अटल

पश्चिम बंगाल में स्वाधीनता के पश्चात पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड और ऐतिहासिक बहुत मिला है। भाजपा ने बंगाल में दो शतक का आंकड़ा पार कर कर एक नई लकीर खींच दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को जहां साल 2016 में 3 और 2021 में 77 सीटें मिलीं। वहां 4 मई 2026 को घोषित हुए चुनाव परिणाम में भाजपा ने 206 सीटों के साथ नया अध्याय लिख दिया है। अंततः भाजपा के लिए कभी असंभव माने जाने वाले पश्चिम बंगाल में भगवा लहरा गया है। भाजपा ने ममता बनर्जी के अभेद्य किले को भेदकर वहां अपना विजय का परचम लहरा दिया है। बीजेपी की ये जीत कई मायनों में विशेष है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिसने भी वहां के जनमानस को देखा, वहां के लोगों के मनोभावों, मुखरता और मौन को देखा। उन्हें ये परिणाम अप्रत्याशित नहीं लगे। क्योंकि 2026 के चुनाव में बंगभूमि में परिवर्तन की लहर सुस्पष्ट दिखाई दे रही थी। हालांकि जिनकी आंखों में वामपंथी, कांग्रेसी और समाजवादी चश्मा लगा था। वो बारंबार ये कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी।

ये जीत केवल ममता बनर्जी को दमनकारी सत्ता की हार नहीं है। बल्कि ये जीत संगठित राजनीतिक अपराध, तुष्टिकरण, माफिया और कट मनी के पूरे सिंडिकेट और माइ्यूत पर जनता का प्रहार है। ये विजय — त्व हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी की जीत है। बंगाल में भाजपा की ये विजय उन असंख्य बलिदानों की विजय है, जिन्होंने अपना जीवन बंगभूमि के स्व के लिए अर्पित कर दिया।ये जीत हिंदुत्व की है। ये जीत राष्ट्रीयता की जीत है। भाजपा की जीत हिंदू समाज की संगठित शक्ति की जीत है। ये विजय बंदेमातरम् की जागृत चेतना का संश्लनाद है। ये जीत इस बात का प्रमाण है कि अन्याय, अत्याचार, हिंसा, रकपात, आतंक का अंत सुनिश्चित है। भाजपा की ये जीत श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे उन सैकड़ों बलिदानियों की जीत है जिन्होंने राष्ट्रीयता के लिए



अपने प्राण न्योछावर कर दिए। कई पीढ़ियां जिस संकल्प में खप गईं। वो अब साकार हो चुका है। क्योंकि वहां का समाज संगठित हुआ। बच्चा-बच्चा राष्ट्रीय अस्मिता का ध्वजवाहक बना। उसका परिणाम भाजपा की प्रचंड जीत हुई।

लेकिन ये जीत केवल पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की ही कहानी बयां नहीं कर रही है बल्कि नए समीकरणों की ओर संकेत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीत के बाद 4 मई 2026 को बीजेपी मुख्यालय नई दिल्ली में अपने संबोधन के दौरान जनादेश के लिए न सिर्फ़ आभार जताया। बल्कि उन्होंने सुस्पष्ट कहा कि— ये जीत भारत के लोकतंत्र और संविधान की जीत है। चुनाव में हार-जीत अलग बात है। लेकिन बदला नहीं बल्कि बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं भविष्य की बात होनी चाहिए।

इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से आह्वान किया कि— हिंसा के अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। बंगाल की सेवा के लिए काम करें। विवाद नहीं विकास, विभाजन नहीं विश्वास चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बंगाल के विकास, सुरक्षा, विकासित भारत के संकल्प को दुहराया। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि दोषियों को सज़ा जरूर मिलेगी। स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए सत्ता नहीं बल्कि उसकी नीति महत्वपूर्ण है। इसके संकेत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दे दिए हैं। यानी पश्चिम बंगाल में वर्षों

के कम्युनिस्ट आतंक, ममता बनर्जी की क्रूरता से त्रस्त जनता अब परिवर्तन की नई दिशा की ओर बढ़ चली है।

वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में वर्षों से चली आ रही राजनीतिक हिंसा, सत्ता के संरक्षण में जारी रहे रकपात, गुंडागर्दी, दुराचार से जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी। ऐसे में भाजपा में जनता को अपना हित दिखा। भाजपा की जीत के कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स की बात करें तो — बीजेपी ने खुद को हिंदुत्व और बंगाली अस्मिता का स्पेक होल्डर और रक्षक बताया। इसके चलते पश्चिम बंगाल में हिन्दू पहचान प्रमुख पहचान बनकर उभरी?। बंगाल के समाज ने इस बात को प्रमुखता दी कि— हमारी अलग-अलग जितनी भी पहचानें हैं। उन सबमें सबसे बड़ी पहचान हिन्दू होने की पहचान है। इसी पर आक्रमण हो रहा है। ऐसे में हिन्दू और हिन्दुत्व के बोध ने बंगाल की अन्तश्चेतना में नया सांस्कृतिक जागरण किया। इसके चलते लोग मुखर हुए।

वहीं पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, सुवेंदु अधिकारी का आक्रामक शैली को लोगों ने दिल में जगह दी। अमित शाह के— 5 मई को टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटकाकर— सीधा कर दूंगा— इस बयान को जनता ने हाथों हाथ लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पीपुल कनेक्ट के हर सांकेतिक प्रतीक को लोगों ने अपने से जोड़ा। चाहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का झालमुड़ी खाने वाला प्रलेपण हो। याकि जनसभा के दौरान खुद मोबाइल निकालकर —उसकी वीडियोग्राफी करनी हो। याकि टीएमसी और ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रामक बयान देना हो। 4 मई दीदी गई के नारे हों। इन सबने जनता को भाजपा के पक्ष में किया।

महिला सुरक्षा के मुद्दे, आर जी कर मेंडिकल कॉलेज, संदेशखाली जैसे मुद्दों को बीजेपी ने चुनाव के केंद्र में ला दिया?। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, अमित शाह से लेकर हर बीजेपी नेता ने महिला सुरक्षा, हिन्दू शिा और डेमोग्राफी बदलाव के मुद्दे को जनता तक ले गए।स्क्रूक केंद्रीय सुरक्षाबलों की तैनाती ने फर्जी

वोटिंग पर लगाम लगाई। भयमुक्त मतदान के चलते भाजपा को सीधा फायदा मिला। वहीं महिलाओं और युवाओं को हर महीने 3 हजार रु देने के वादों ने भी भाजपा को बढ़त दिलाई।

मुस्लिम तुष्टिकरण के आकंट तक डूबी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में हिन्दुओं के साथ कुठाराघात किया?। हिन्दू त्योहारों पर प्रतिबंध, मुस्लिमों को खैरात पर खैरात। हिन्दुओं के खिलाफ होने वाली सुनियोजित हिंसा पर ममता बनर्जी के मौन ने— वहां के समाज को उद्धेलित किया। पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं की घुसपैट की ममता बनर्जी के मौन समर्थन ने खूब तुल दिया। इससे बंगाल के लोगों के मन में भय का वातावरण बना। चहुँओर हिंसा, रकपात, गुंडागर्दी, गौ हत्या, गौ-तस्करी, माफियाओं के बढ़ते हौसलों ने ममता के शासन के अंत की पटकथा लिख दी। बांग्लादेश में शेरु हसीना के तख्तापलट के बाद से वहां हिन्दुओं के खलिाफ हुई सुनियोजित हिंसा और हर समय ममता बनर्जी का मौन रहना। मुस्लिमों की वकील बनकर सामने आना। ये सब पश्चिम बंगाल की जनता ने देखा। वो उससे सीधे प्रभावित हुए। फिर अपना धैर्य बनाए रखा और मतदान के दिन बदला ले लिया।

बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों को डेमोग्राफी में हुए अप्रत्याशित परिवर्तन ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। मुर्शिदाबाद हिंसा के साथ ही मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं के साथ हुई हिंसा में भी ममता का चुप रहना। कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं की बढ़ती अराजकता ने ममता के प्रति लोगों की सहायुभूति ख़ुत्म कर दी?। वहीं चुनाव के पूर्व मालदा में सुप्रिम कोर्ट की ओर से एसआईआर के काम में लगे न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक बनाने की घटना ने पूरे देश का अपनी ओर ध्यान खींचा। देर रात को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद सेना ने जब रेस्क्यू किया तब जाकर न्यायिक अधिकारियों की जान बची। इन सारे घटनाक्रमों को पश्चिम बंगाल समेत देश की जनता देख रही थी ?

आज का इतिहास

- 1832 यूनाय नु ने स्वतंत्रता हासिल की, बावारिया के सम्राट चुना गया ।
- 1864 दुनिया का सबसे पुराना जीवित क्लिपर जहाज, सिटी ऑफ एडेलदेवास, विलियम पाइल, हे एंड कंपनी द्वारा सुंदरलैंड, इंग्लैंड में लॉन्च किया गया, यात्रियों और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच सामानों की आपूर्ति करता है।
- 1875 जापान और रूस के बीच सेंट पीटर्सबर्ग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ।
- 1895 अलेक्जेंडर स्टेपानोविच पोपोव ने अपने रेडियो रिसीवर को प्रस्तुत किया, जिसे लाइटनिंग डिटेक्टर के रूप में परिष्कृत किया गया, रूसी भौतिक और रासायनिक सुरक्षा के लिए ।
- 1920 पोलिश-सोवियत युद्ध-कीव आक्रामक के दौरान, पोलिश सैनिकों ने एक प्रतीकात्मक यूक्रेनी बल को मदद से, कीव पर कब्जा कर लिया, केवल एक महीने बाद सोवियत रेड आर्मी द्वारा आक्रामक रूप से संचालित होने के लिए ।
- 1934 पर्ल ऑफ लाओ त्जु, दुनिया का सबसे बड़ा मोती, 7 मई 1934 को पालवन सागर, फिलीपींस में पाया गया था। इसका व्यास 24 सेंटीमीटर है और वजन 6.4 किलोग्राम है, हालांकि इसे रत्न मोती के रूप में नहीं माना जाता है। इसे पर्ल ऑफ अल्लाह भी कहा जाता है।
- 1940 ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बहस शुरू हुई और कई दिनों बाद विंस्टनचर्चिल के साथ प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन के प्रतिस्थापन का समापन हुआ ।
- 1946 मासारू इबुका और एकियो मोरीटा ने टोक्यो टेलीकॉम इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना की, जिसने बाद में इसका नाम बदलकर सोनी कर दिया ।
- 1952 जेफ्री डब्ल्यू एडम्स ने 7 मई, 1952 को वाशिंगटन, डी.सी. में एकीकृत सर्फिट का विचार जनता के सामने प्रस्तुत किया। हालांकि वह वह था जिसने आईसी के विचार को 1956 में इस तरह के सर्किट का निर्माण करने में विफल कर दिया था ।
- 1960 शीत युद्ध-सोवियत नेता निकिता ख़श्चेव ने घोषणा की कि उनका देश अमेरिकी पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स को पकड़ रहा है, जिनके -2 जासूस विमान को छह दिन पहले सोवियत संघ में मार गिराया गया था ।
- 1964 प्रशांत एयर लाईंस फ्लाइट 773 संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन रेमन के पास 7 मई, 1964 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यह संयुक्त राज्य के इतिहास में सामूहिक हत्या की आत्महत्या का पहला मामला था। फ्रांसिस्को पाउला गॉजालेस ने खुद से पहले पायलट और साह-पायलट दोनों को गोली मार दी, दुर्घटना में सभी 44 यात्री मारे गए ।

सियासत का नया त्याकरण लिखता जनादेश 2026

योगेश कुमार गोयल

2026 के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में केवल सत्ता परिवर्तन या सत्ता वापसी की घटना मात्र नहीं हैं बल्कि ये देश की राजनैतिक दिशा और मतदाता के बदलते मनोविज्ञान का एक ऐसा विस्तृत दस्तावेज हैं, जिसने भविष्य की राजनीति के लिए नए प्रतिमान स्थापित कर दिए हैं। इन परिणामों ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय मतदाता अब केवल भावनात्मक नारों या पारंपरिक वोट बैंक के गणित में उलझने वाला नहीं है बल्कि वह शासन की जवाबदेही, नेतृत्व की विश्वसनीयता और विकास के ठोस धरातल पर अपना निर्णय सुना रहा है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण के तटीय मैदानों तक फैली इस राजनैतिक हलचल का यदि सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो यह साफ दिखाई देता है कि ‘भावा’ राजनीति का पूर्वी विस्तार अब अपने चरम पर है जबकि दक्षिण में क्षेत्रीय अस्मिता और नए राजनैतिक विजन के बीच एक दिलचस्प संघर्ष छिड़ गया है। ये चुनाव परिणाम उन तमाम राजनैतिक पंडितों के लिए एक सबक हैं, जो केवल पुराने आंकड़ों के आधार पर भविष्यवाणियाँ करते थे क्योंकि इस बार मतदाताओं ने एक ऐसी ‘परिवर्तन की आंधी’ का सूत्रपात किया है, जिसने कई दिग्गजों के राजनैतिक भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए ‘महाभूकंप’ को देखे बिना 2026 के इस

जनादेश की व्याख्या अधूरी है। लगभग डेढ़ दशक से राज्य की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस का ढहना और भाजपा का 150 सीटों के पार जाना यह दर्शाता है कि बंगाल की जनता ‘सिंडिकेट राज’ और ‘कट मनी’ की संस्कृति से ऊब चुकी थी। बंगाल का यह परिणाम केवल एक चुनावी जीत नहीं बल्कि एक वैचारिक क्रांति है, जहां मतदाताओं ने ‘बंगाली अस्मिता’ के साथ ‘राष्ट्रीय विकास’ के समन्वय को स्वीकार किया है। संदेशखाली जैसी घटनाओं ने शासन के प्रति जो आक्रोश पैदा किया था, वह ईवीएम के माध्यम से ज्वालामुखी की तरह फटा। भाजपा ने यहां जिस प्रकार से हिंदू मतों का ध्ववीकरण किया और साथ ही मनुआ एवं राजवंशी समुदायों को अपने पक्ष में संगठित किया, उसने टीएमसी के अभेद्य दुर्ग की ईट से ईट बजा दी। ग्रामीण बंगाल में ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ और ‘जल जीवन मिशन’ जैसी केंद्रीय योजनाओं ने एक नया ‘लाभार्थी वर्ग’ तैयार किया, जिसने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की पारदर्शिता को राज्य सरकार की भ्रष्टाचार युक्त मशीनरी से बेहतर पाया। यह चुनाव परिणाम ममता बनर्जी के उस करिश्मे के अंत का भी संकेत है, जो कभी अपराजेय माना जाता था और अब बंगाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां सुशासन और कानून-व्यवस्था ही सत्ता की एकमात्र कसौटी रह गई है।

असम की ओर रुख करें तो यहां की स्थिति बंगाल से बिल्कुल भिन्न लेकिन उतनी ही प्रभावशाली है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा



सरमा के नेतृत्व में भाजपा की ‘हैट्रिक’ ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब विकास को सांस्कृतिक अस्मिता के साथ जोड़ दिया जाता है तो वह एक अजेय फॉर्मूला बन जाता है। असम में भाजपा की जीत केवल सत्ता की निरंतरता नहीं है बल्कि यह उस विश्वास की पुष्टि है, जो जनता ने सरमा के प्रभावी और साहसी नेतृत्व में दिखाया है। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन ने राजनैतिक भूगोल को इस तरह बदला कि चुसपैठ और बाहरी प्रभाव की राजनीति हाथिए पर चली गई और ‘असमिया राष्ट्रवाद’ का नया स्वरूप उभरकर सामने आया। ‘ओरुनोडोई’ जैसी योजनाओं ने महिला मतदाताओं के बीच भाजपा को एक ऐसे रक्षक के रूप में स्थापित कर दिया है, जिसके पास उनके दैनिक जीवन की समस्याओं का ठोस समाधान है। असम का जनादेश संदेश देता है कि यदि नेतृत्व के पास विजन हो और वह जमीनी मुद्दों पर आक्रामक तरीके से कार्य करे तो जनता उसे फिर सेवा का अवसर प्रदान करती है। यहां विपक्ष की बिखरी हुई ताकत और कांग्रेस की वैचारिक शून्यता ने भाजपा की राह को और भी आसान बना दिया, जिससे यह

स्पष्ट हो गया कि पूर्वोत्तर में भाजपा अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक स्थायी शक्ति बन चुकी है।

दक्षिण भारत के राजनैतिक परिदृश्य में तमिलनाडु ने इस बार पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। थलपति विजय के रूप में एक नए राजनैतिक सूर्य का उदय यह बताता है कि तमिलनाडु की जनता अब डीएमके और एआईएडीएमके के दशकों पुराने द्वंद्व से मुक्ति चाहती थी। विजय की पार्टी ‘तमिलगाम वेत्री कड़गम’ द्वारा 100 सीटों का आंकड़ा पार करना एक राजनैतिक चमत्कार है, जिसने एनडीए के उस दौर की याद ताजा कर दी, जब सिनेमा और राजनीति का संगम सत्ता की चाबी बन गया था। विजय ने खुद को केवल एक फिल्मी सिंतारे के रूप में नहीं, एक ‘संकटमोचक’ और ‘युवा आइकन’ के रूप में पेश किया। उन्होंने गठबंधन की राजनीति को ठेंगा दिखाते हुए ‘अकेले शेर’ की तरह चुनावी मैदान में उतरने का जो साहस दिखाया, उसने तमिल युवाओं के बीच एक नई ऊर्जा का संचार किया। यह परिणाम कमल हासन और विजयकांत जैसे पूर्ववर्ती सिंतारों की तुलना में कहीं अधिक गहरा है क्योंकि विजय ने ‘बौद्धिक राजनीति’ के बजाय ‘जमीनी और मास-अपील’ वाली राजनीति को चुना। तमिलनाडु का यह जनादेश द्रविड़ राजनीति के भविष्य को एक नई दिशा देने वाला है, जहां अब ‘तीसरी शक्ति’ केवल संभावना नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुकी है।

केरल का चुनाव परिणाम भी कम

दिलचस्प नहीं रहा, जहां ‘एक बार इधर, एक बार उधर’ की पारंपरिक रीत ने पिनारई विजयन की तमाम कोशिशों के बावजूद एलडीएफ को सत्ता से बाहर कर दिया। यूडीएफ की यह प्रचंड वापसी यह दर्शाती है कि केरल का शिक्षित मतदाता भ्रष्टाचार और राजकोपीय कुप्रबंधन को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था। विभिन्न घोटालों ने एलडीएफ की नैतिक साख को जो चोट पहुंचाई, उसकी भरपाई उसकी जनहितैथी योजनाओं से भी नहीं हो सकी। राहुल गांधी की वायनाडु में सक्रियता और ‘न्याय’ जैसी योजनाओं के वादे ने कांग्रेस नीत यूडीएफ के पक्ष में एक सकारात्मक माहौल बनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच उभजे असंतोष ने सत्ता के संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ दिया। केरल का मतदाता यह संदेश दे रहा है कि वह किसी भी दल को ‘टेकन फॉर ग्रांटेड’ नहीं लेता और सत्ता की चाबी हमेशा जनता के हाथ में रहती है, जो हर पांच साल में शासन की समीक्षा बड़ी निर्ममता से करती है।

पुडुचेरी जैसे छोटे केंद्रशासित प्रदेश ने भी यह दिखाया कि राजनीति में स्थिरता और केंद्र के साथ तालमेल का कितना महत्व है। एन. रंगारामो की सहज छवि और भाजपा के साथ उनके गठबंधन ने मतदाताओं को यह भरोसा दिलाया कि विकास के लिए केंद्र और स्थानीय सरकार का एक पटरी पर होना जरूरी है। पुडुचेरी के परिणामों ने यह साबित किया कि छोटे क्षेत्रों में व्यक्तिगत संपर्क और सामाजिक

समीकरण ही हार-जीत की रेखा खींचते हैं। यहां का मतदाता प्रशासनिक गतिरोध के बजाय स्थिरता को अधिक महत्व देता है और यहीं कारण रहा कि गठबंधन की राजनीति ने यहां अपनी सफलता का परचम फहराया।

पांचों राज्यों के परिणामों को यदि एक व्यापक कैनवास पर रखकर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि भारतीय राजनीति अब ‘परफॉर्मंस’ के युग में प्रवेश कर चुकी है। अब केवल जातिगत समीकरण बैठाकर या बड़े-बड़े विज्ञापन देकर चुनाव नहीं जीते जा सकते। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत और असम में उसकी वापसी दर्शाती है कि ‘हिंदुत्व’ और ‘विकास’ का मिश्रण अभी भी भारतीय राजनीति का सबसे शक्तिशाली तत्व है लेकिन तमिलनाडु और केरल के परिणाम ममता के सचेत करते हैं कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं और स्थानीय नेतृत्व का महत्व कभी कम नहीं होगा। इन चुनावों ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के लिए केरल में संजीवनी का काम किया है तो वहीं भाजपा के लिए दक्षिण में नए मित्र तलाशने की चुनौती पेश की है। कुल मिलाकर, 2026 के इस जनादेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मतदाता अब अधिक अपेक्षा-केंद्रित हो गया है। वह केवल यह नहीं देखता कि सरकार ने क्या किया बल्कि यह भी देखता है कि नेतृत्व कितना विश्वसनीय है और भविष्य के लिए उसके पास क्या रोडमैप है। थलपति विजय जैसे नए चेहरों का स्वागत और ममता बनर्जी जैसे कढ़ावर नेताओं की हार बताती है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है।

राहुल का ममता पर हमला इंडिया गठबंधन के लिए साबित हुआ आत्मघाती

रशीद किदवई

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम कांग्रेस के लिए किसी बड़े राजनीतिक सपने से कम नहीं हैं। केरल को छोड़कर, जहां वाम मोर्चे के खिलाफ दस साल की एंटी-इनकम्बेंसी के चलते कांग्रेसनीत यूडीएफ की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी, शेष चार राज्यों के नतीजों ने पार्टी की सांगठनिक कमजोरियों की पोल खोलकर रख दी है। इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस न तो अपनी पुरानी गलतियों से सबक ले रही है और न ही जोखिम उठाकर नई रणनीति बनाने का साहस दिखा पा रही है। यह न केवल कांग्रेस, बल्कि पूरे इंडिया ब्लॉक के लिए करारा झटका है, जिससे उबरना उसके लिए काफी मुश्किल होगा। पश्चिम बंगाल और असम में कांग्रेस ने जैसा प्रदर्शन किया, वह काफी हद तक अपेक्षित भी था, लेकिन तमिलनाडु के नतीजों ने कांग्रेस नेतृत्व की भारी रणनीतिक खामियों को उजागर कर दिया है। अवरज तो इस बात को लेकर है कि पार्टी नेतृत्व राज्य में द्रमुक के खिलाफ पनप रहे सत्ता विरोधी रुझान को भापने में हर स्तर पर विफल रहा। कांग्रेस के आंतरिक सबै भी राज्य में अभिनेता विजय की नई पार्टी ‘तमिलगाम वेत्री कड़गम’ (टीवीके) के एक मजबूत ताकत के रूप में उभरने के संकेत दे रहे थे। कांग्रेस के साथ टीवीके के साथ गठबंधन करने का तब एक सुनहरा अवसर भी था, जब खुद विजय के पिता एसए चंद्रशेखर ने साल की शुरुआत में स्वयं गठबंधन करने का प्रस्ताव दिया था। विजय की पार्टी के साथ चुनावी तालमेल करने की जोरदार पेशी करने वाले कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने चुनाव नतीजों के तुरंत बाद एक टीवी चैनल पर कहा भी कि हमने राज्य में एक बड़ा मौका गंवा दिया। उनके मुताबिक, अगर राज्य में कांग्रेस और टीवीके के बीच गठबंधन होता, तो राहुल गांधी और विजय की

जोड़ी राज्य में दो-तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में आती। बकौल चक्रवर्ती, राज्य के युवा मतदाता बदलाव चाहते थे। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता पुरानी वफादारी पर अड़ गए। राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व ने भी पी चिदंबरम जैसे कुछ दिग्गज कांग्रेस नेताओं की सलाह को तर्जोह दी और टीवीके के साथ गठबंधन करने का साहस नहीं दिखा पाए। असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के प्रखर हिंदुत्ववादी एजेंडे का मुकामला करना कांग्रेस के लिए पहले से ही आसान नहीं था, लेकिन पार्टी वहां कुछ बेहतर करने की अपेक्षा तो रख सकती थी। किंतु, समस्या यह थी कि वहां भाजपा से लड़ने के बजाय पार्टी के वरिष्ठ नेता आपस में ही सिर-फुटव्वल में लगे रहे। किसी राज्य में चुनावी सफलता के लिए प्रदेश इकाई में जिस तालमेल की दरकार होती है, वह असम में गायब था। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के राज्य प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई के बीच एक तरह से संवादहीनता की स्थिति बनी रही। केंद्रीय नेतृत्व ने भी समय रहते दखल नहीं दिया, मानो उसने उचित नियति को पहले ही स्वीकार कर लिया, जो आज ईवीएम खुलने के बाद सामने आई है। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दूसरे चरण में राहुल गांधी द्वारा ममता बनर्जी पर किया गया सीधा हमला इंडिया गठबंधन के लिए आत्मघाती साबित हुआ। ममता की टीबी आलोचना ने भाजपा विरोधी वोटों को विभाजित कर दिया, जिसका सीधा लाभ भाजपा को मिला। हालांकि, ममता की हार का श्रेय भाजपा के सुनियोजित चुनावी प्रबंधन को ज्ञानदा दिया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की रणनीति ने इस पराजय को और विराट बना दिया। भाजपा ने हिंदुत्व का जो नरेशन गढ़ लिया है, उसकी कोई प्रभावी काट किसी भी विपक्षी दल के पास दिखाई नहीं देती। तृणमूल और द्रमुक की इस जबर्दस्त हार के बाद विपक्ष की रही-सही उम्मीद भी चली गई है।

ममता-स्टालिन की हार से डगमगाई विपक्ष की इमारत

आरती आर जेय

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा की शानदार जीत भारतीय राजनीति में एक जबर्दस्त बदलाव का संकेत है। यह न केवल तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी, जो आज देश की सबसे कढ़ावर महिला नेता हैं, की विदाई का प्रतीक है, बल्कि यह संभवतः क्षेत्रीय दलों और उनकी उप-राष्ट्रवाद तथा स्थानीय सांस्कृतिक पहचान की राजनीति के अंत की शुरुआत भी है। इसलिए, पश्चिम बंगाल का ‘भगवाकरण’ भाजपा के प्रभाव क्षेत्र में एक और राज्य के जुड़ने से कहीं ज्यादा है। यह एक धार्मिक-राजनीतिक विचारधारा के रूप में ‘हिंदुत्व’ की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।

ममता बनर्जी की पार्टी की हार, जिसे तमिलनाडु के कढ़ावर क्षेत्रीय नेता एमके स्टालिन और द्रमुक की हार के साथ मिलाकर देखा जाए, इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इसके दो सबसे मजबूत स्तंभ ढह गए हैं, जिससे विपक्ष की पूरी इमारत कमजोर और डगमगाती हुई रह गई है। जाहिर है, अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में इसका असर जरूर दिखेगा, जहां ‘इंडिया’ गठबंधन के एक और अहम स्तंभ (अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी) के सामने अब एक मुश्किल चुनौती है: भाजपा के खिलाफ लड़ाई में अपने कार्यकर्ताओं के गिरते मनोबल को बढ़ाना।

भले ही इस बात को लेकर सवाल उठते रहेंगे कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों की जल्दबाजी में की गई ‘विशेष गहन समीक्षा’ (एसआईआर) और 2.5 लाख अर्धसैनिक बलों की तैनाती जैसे सरकारी हस्तक्षेपों का चुनाव परिणामों पर क्या असर पड़ा, लेकिन एक ऐसे राज्य में, जहां लंबे समय से वामपंथी राजनीति का दबदबा रहा है (पहले माकपा और फिर बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का), यह पहली बार होगा, जब भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बहुमत वाली सरकार की कमान संभालेगा। एसआईआर के दौरान लगभग 90 लाख नमूने हटा दिए गए थे, जिनमें से 27 लाख नामों को ‘जांच के अधीन’ सूची में डाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने सत्यापन के लिए जो दस्तावेज जमा किए थे, उनमें तकनीकी त्रुटियां थीं। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो विवाद लगातार बने रहे हैं,



उनका कोई संक्षिप्त जवाब नहीं है। हालांकि, दो बातें साफ हैं। पहली यह कि ममता ने भाजपा के हर हमले का जिस जोरदार और जोशिले अंदाज में मुकामला किया, वह तारीफ के काबिल है। यहां तक कि उनके आलोचकों को भी मानना पड़ेगा कि उन्होंने अपने ‘बंगाल की शेरनी’ उपनाम को पूरी तरह से सही साबित किया। उन्होंने यह दिखा दिया कि वह ऐसी इंसान नहीं हैं, जो आसानी से किसी के आगे झुक जाएं। आखिरकार, उन्होंने पश्चिम बंगाल की सड़कों पर कई दशकों तक वाम मोर्चा की सरकार से लोहा लेते हुए अपनी पहचान बनाई है। दूसरी बात यह है कि 2021 के चुनावों में उनसे करारी हार मिलने के बाद, भाजपा ने उनकी हार की पटकथा बेहद बारीकी से तैयार की। पार्टी ने जमीनी स्तर पर मतदान के रुझान का विस्तृत अध्ययन करने के लिए काम शुरू कर दिया, जिसमें आरएसएस ने भी मदद की। हर निर्वाचन क्षेत्र का नक्शा तैयार किया गया, कमजोर क्षेत्रों की पहचान की गई, लोगों के मिजाज का लगातार सर्वेक्षण किया गया और एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। भाजपा ने दो ऐसे कारकों का लाभ उठाया, जो ऊपरी तौर पर स्पष्ट नहीं थे। पहला, तृणमूल कांग्रेस के प्रति बढ़ता असंतोष; और दूसरा, वह कार्यप्रणाली, जिसे तृणमूल ने वामपंथियों से हूबहू अपना लिया था, यानी फुटबाल क्लबों, सामाजिक और सांस्कृतिक समितियों में बाहुबलियों के स्थानीय दस्तों को पालना-पोसना।

दिलचस्प बात है कि जहां एक ओर ममता खुद बेहद लोकप्रिय बनी हुई हैं, खासकर महिलाओं के बीच, वहीं मौजूदा विधायकों और पूरी सरकार के खिलाफ सत्ता-

विरोधी लहर साफ तौर पर मौजूद थी। इसे राज्य के बाहर से आए पत्रकारों ने तो भांप लिया, लेकिन बंगाल में रहने वाले इसे समझने से चूक गए। हालांकि, ममता ने सत्ता-विरोधी लहर का मुकामला करने के लिए अपने मौजूदा विधायकों में से लगभग 40 फीसदी को बदल दिया था, लेकिन भाजपा ने लोगों की नाराजगी को पहले ही भांप लिया था तथा उसे और हवा दी। दूसरी बात थी बंगाली हिंदुओं में छिपा हुआ इस्लामोफोबिया। भाजपा घुसपैठियों (बांग्लादेशी मुसलमानों) के बारे में लगातार अभियान चलाकर बता रही थी कि किस तरह वे ममता की मदद से पश्चिम बंगाल की आबादी का ढांचा बदल रहे हैं। इस अभियान न केवल बंगाली ‘भद्रलोक’ को प्रभावित किया, जो उदारवादी परंपराओं को बहुत पहले ही भुला चुके हैं, बल्कि उन महत्वाकांक्षी ग्रामीणों को भी अपनी ओर खींचा, जो बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और विकास के अवसरों की कमी के बोझ तले दबे थे। ये ग्रामीण लोग अपनी असंतुष्टि के लिए मोदी सरकार के बजाय, तृणमूल सरकार को जिम्मेदार ठहराने चलाए।

बंगाल में भाजपा की शानदार जीत का श्रेय काफी हद तक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को जाता है, जो लगभग एक महीने तक पश्चिम बंगाल में ही डटे रहे और चुनावी गतिविधियों पर नजर रखते रहे। भाजपा के बारे में यह कहा जाता है कि एक बार किसी राज्य पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लेने के बाद, वह उसे कभी नहीं गंवाती।

आज, भाजपा के प्रभुत्व का दायारा पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर, उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों से होते हुए पूर्व में पश्चिम बंगाल और असम तक, और देश के सबसे पूर्वोत्तर छोर तक फैला हुआ है, जहां वह स्थानीय पार्टियों के साथ गठबंधन सरकारों में सत्ता में है। इससे उसे अपनी पूरी ताकत दक्षिणी राज्यों को जीतने पर लगाने की आजादी मिल जाती है। इन पांच राज्यों में तय (केरल, तेलंगाना और कर्नाटक) में उसका मुख्य मुकामला कांग्रेस से है, जो उत्तर भारत में ‘भावा लहर’ को रोकने में ज्यादातर नाकाम रही रही है। पश्चिम बंगाल में ‘भगवा लहर’ इस बात को रेखांकित करती है कि भारत बदल रहा है। यहां के सामाजिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक परिदृश्य में एक समतलीकरण देखने को मिल रहा है, जो भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति को बल प्रदान करता है।

क्या भारतीय राजनीति में क्षत्रपों का अंत हो रहा है?

तिनोद पाठक

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर देशभर में एक तेज बहस चल रही है। कोई इसे भारतीय राजनीति का महा परिवर्तन बता रहा है तो कोई इसे सामान्य सत्ता परिवर्तन का हिस्सा मान रहा है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के जनादेश ने निश्चित रूप से राजनीतिक समीकरणों को झकझोर दिया है। क्या यह वाकई उस बड़े बदलाव की शुरुआत है, जिसका दावा किया जा रहा है? या फिर यह सिर्फ बदलती जनभावनाओं का एक और पड़ाव है?

दरअसल, 2024 के लोकसभा चुनावों में भले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनावों के नतीजों से स्पष्ट है कि अब वो लगभग अजेय हो चली है। देश में अब भाजपा और एनडीए की 22 राज्यों में सरकारें हैं।

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन जैसे मजबूत नेताओं को झटका लगाना निश्चित ही एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। क्या इसे क्षत्रपों का अंत कहना सही होगा? ममता बनर्जी ने वर्षों तक बंगाल की राजनीति को अपनी शैली में गढ़ा। अगर जनता ने उनसे दूरी बनाई है तो क्या यह उनके राजनीतिक मॉडल की विफलता है या शासन के लंबे दौर की स्वाभाविक थकान? क्या भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सवालोंने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया या फिर मतदाता अब नए विकल्प की तलाश में है? तमिलनाडु में भी सवाल कुछ अलग नहीं हैं। एम.के. स्टालिन के द्रविड़ मॉडल को चुनौती मिलना क्या उस विचारधारा के कमजोर होने का संकेत है या फिर यह नेतृत्व और कार्यशैली के प्रति असंतोष का परिणाम है? अगर विजय और उनकी पार्टी तमिलगाम वेत्री कड़गम (टीवीके) उभर रही है तो क्या यह स्थाई बदलाव है या केवल एक चुनावी आकर्षण?

केरलम में कांग्रेस गठबंधन की सरकार दस साल बाद सत्ता में लौट रही है। कांग्रेस के लिए प्रयत्नाता का विषय



यह है कि अब चार राज्यों में उसकी सरकार है, जबकि वामदल अब देश के किसी भी राज्य में नहीं हैं। स्पष्ट है कि उनके विचार को जनता ने नकार दिया है। पंद्रह साल पहले वामदलों की पश्चिम बंगाल में सरकार थी, जो 34 साल के रिकॉर्ड समय तक चली, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में वो गायब हो गई है। केवल भारत नहीं, करीब-करीब पूरी दुनिया में वाम विचारधारा की यही स्थिति है। केरलम की हार और पश्चिम बंगाल में अपनी दुर्दशा पर वाम पार्टियां निश्चित रूप से आत्ममंथन करेंगी। असम में हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की लगातार सफलता को अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां भी एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या भाजपा की जीत उसकी अपनी ताकत का परिणाम है या विपक्ष की कमजोरी का? निश्चित रूप से हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य में मजबूत नेतृत्व दिया है। उनकी सक्रियता, आक्रामक शैली और स्थानीय मुद्दों पर पकड़ ने भाजपा को बढ़त दिलाई है, लेकिन क्या यही पूरी कहानी है?

क्या कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी और स्पष्ट नेतृत्व की कमी ने भाजपा की राह आसान नहीं कर दी? गौरव गोगोई जैसे नेताओं की हार को क्या केवल विरासत की राजनीति की असाफलता कहा जा सकता है या यह कांग्रेस के भीतर गहरे संकट की ओर इशारा करता है? जहां तक विवादित आरोपों, जैसे तथाकथित पाकिस्तान कनेक्शन का सवाल है, क्या ऐसे मुद्दे वास्तव में मतदाता को प्रभावित करते हैं? या फिर ये केवल चुनावी शोर

बनकर रह जाते हैं, जो कभी-कभी उल्टा असर भी छोड़ जाते हैं? इन चुनावी नतीजों के बाद यह कहना आसान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक वर्चस्व और मजबूत हो गया है। अमित शाह की रणनीतियां लगातार सफल होती दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल में विजय का बड़ा श्रेय राजनीति के चाणक्य अमित शाह को ही जाता है। उन्होंने ममता बनर्जी को जैसी व्यूहरचना की, उसकी शायद ही किसी को उम्मीद थी। इन नतीजों का क्या अर्थ यह है कि राष्ट्रीय राजनीति की धुरी पूरी तरह बदल गई है?

क्या भारत जैसे विविध देश में एक ही राजनीतिक रुझान सभी राज्यों पर लागू हो सकता है? केरल जैसे राज्यों में अलग राजनीतिक व्यवहार देखने को मिलता है। दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों में भी मतदाता अलग-अलग मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। ऐसे में क्या यह कहना सही होगा कि विपक्ष पूरी तरह अप्रासंगिक हो गया है? या फिर वह केवल संक्रमण के दौर से गुजर रहा है? राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं, लेकिन क्या समस्या केवल नेतृत्व की है? या फिर यह संगठन, रणनीति और जमीनी जुड़ाव की भी है? इंडी गठबंधन का भविष्य भी इन नतीजों के बाद अनिश्चित दिखाई देता है। अगर क्षेत्रीय दल कमजोर होते हैं और कांग्रेस मजबूत विकल्प नहीं बन पाती तो विपक्ष की राजनीति किस दिशा में जाएगी? लेकिन राजनीति में हर संकट एक अवसर भी होता है। क्या कांग्रेस इस हार को आत्ममंथन का आधार बनाएगी या फिर यह गिरावट आगे भी जारी रहेगी? पांच राज्यों के ये नतीजे निश्चित रूप से यह बताते हैं कि भारतीय मतदाता अब पहले से कहीं अधिक जागरूक और मांग करने वाला हो गया है। वह केवल भावनात्मक नारों से संतुष्ट नहीं है। उसे परिणाम चाहिए। स्थिरता चाहिए। नेतृत्व में स्पष्टता चाहिए। लेकिन, क्या यह महा-परिवर्तन है? शायद नहीं। क्या यह बदलाव का संकेत है? निश्चित रूप से हां। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह रुझान आने वाले वर्षों में स्थाई रूप लेगा या भारतीय राजनीति एक बार फिर नए संतुलन की ओर लौट जाएगी?

तमिलनाडु में विजय ने भेदी द्रविड़ राजनीतिक दलों की दीवार

आर. राज्ञोपालन

सोमवार, चार मई का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में एक स्वर्णिम दिवस के रूप में दर्ज होगा। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस को शिकस्त देकर पहली बार अपनी जीत दर्ज कर इतिहास रचा है, वहीं तमिलनाडु में दशकों से सत्ता में रहे दोनों द्रविड़ राजनीतिक दलों की दीवार को भेदकर अभिनेता विजय ने नायक के रूप में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ, तो भाजपा के नेतृत्व में एनडीए ने असम व पुडुचेरी में अपना परचम लहराया है। दक्षिण भारतीय सुपरस्टार जोसेफ विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से राजनीतिक पंडितों तक को हैरान कर दिया है। फिल्मों में सफलता के बाद राजनीति में प्रवेश करने वाले विजय, जिन्हें उनके प्रशंसक ‘थलापति’ कहते हैं, हिंदी भाषी इलाकों में भी काफी लोकप्रिय हैं। 22 जून, 1974 को जन्मे विजय के पिता एसए चंद्रशेखर तमिल सिनेमा के प्रतिष्ठित निर्देशक रहे हैं, तो मां शोभा एक गायिका थीं। फिल्मी माहौल में जन्मे और पले-बढ़े विजय की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम दिलचस्प नहीं है। स्टारडम हासिल करने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। फिर, राजनीति में उतरे, तो नतीजा सबके सामने है। विजय के नेतृत्व वाली पार्टी ‘तमिलगाम वेत्री कड़गम’ (टीवीके) ने द्रमुक को जड़ से खत्म करने का जो प्रण किया था, उसे प्रभावी ढंग से पूरा करके भी दिखाया है। विजय के गुस्से की वजह थी कि द्रमुक ने टीवीके को कुचलने की कोशिश की थी। पहला कारण था कर्सर में हुई भगदड़। दूसरा, ‘जन नायगम’ फिल्म की



रिलीज को रोकना। और तीसरा, पत्नी संगीता का विजय से अलग हो जाना। संगीता ने तलाक के लिए अर्जी दी थी। वह हलफनामा लीक हो गया था। विजय को शक है कि इन सबके पीछे द्रमुक का ही हाथ था। तमिलनाडु में भ्रष्टाचार, नशे की समस्या, हत्या, बलात्कार और कानून-व्यवस्था की विफलता ने सत्तारूढ़ द्रमुक को सत्ता से बेदखल कर दिया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का खराब शासन और उनके दामाद की लूट-खसोट बेनकाब हो गई। इसके अलावा, वीसीके, डीएमएफके और एमडीएमके जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के प्रभाव ने भी द्रमुक के वोट प्रतिशत को कम किया। सनातन धर्म को ‘डेंगू’ और ‘कोरोना’ बताने वाले उदयनिधि के नफरती बयान पर गृहमंत्री अमित शाह की जोरदार प्रतिक्रिया की वजह से तमिलनाडु और पुडुचेरी में वोटों का ध्ववीकरण हुआ। द्रमुक के खिलाफ सत्ता-विरोधी लहर भी जुड़ गई है। स्टालिन ने मोदी के खिलाफ नकारात्मक चुनावी अभियान चलाया, लेकिन अपनी सीट पर भी हार गए। पुडुचेरी में राजग ने अच्छा प्रदर्शन किया है। भाजपा का गठबंधन एनआर कांग्रेस के साथ था, जिसने पिछले पांच वर्षों में सबसे बेहतरान प्रदर्शन किया था। मतदाताओं ने राजग को जनादेश दिया है। चार मई का फैसला तमिलनाडु के 39 संसदों के लिए भी एक जनमत संग्रह है कि उन्होंने आठ करोड़ तमिल लोगों की किस तरह से सेव की है।

शादी में बारिश का होना कैसा शगुन होता है



मौसम कैसा होगा—सबको चिंता होती है कि कहीं बारिश आफत ना बन जाये। लोगों को चिंता रहती है उस दिन मौसम खराब या अप्रत्याशित ना हो जाये इसलिए लोग भावी मौसम की भविष्यवाणी जानते रहते हैं। शादी है खुशी का दिन—आपकी शादी का दिन आपके जीवन का सबसे खुशी का दिन होना चाहिए। यह दिन प्यार, खुशी, आशा, उम्मीद, और उत्साह से भरा हुआ होना चाहिए। बारिश फलदायी है—बारिश से सूखे स्थानों को पानी मिलता है, फसलें लहलहाती हैं, इस प्रकार बारिश फलदायी है और

इसे अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसे ध्यान रखते हुये शादी के दिन होने वाली बारिश को अच्छी किस्मत की निशानी माना जाता है। बारिश कई अच्छी चीजों की प्रतीक है—आपके जीवन के इस खास दिन पर होने वाली बारिश को कई कारणों से अच्छे भाग्य की निशानी माना जाता है। बारिश आशीर्वाद, सफाई, एकता, और एक नई शुरुआत की प्रतीक है। कुछ संस्कृतियों में इसे परिवार के बढने की प्रतीक भी माना जाता है। इन सभी सकारात्मक कारणों से शादी के दिन होने वाली बारिश को अच्छे भाग्य माना जाता है।

आपका क्या मानना है। आशा और आशीर्वाद—बारिश आशीर्वाद की प्रतीक है, और हर कोई अपनी शादी में आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। आशीर्वाद आशा और समर्थन का सूचक है। जब आप एक नई संभावनाओं के साथ नई शुरुआत करने जा रहे हों तो आपको आशावादी जरूर होना चाहिए। समृद्धि—आशीर्वाद, शारीरिक और भौतिक दोनों अर्थों में समृद्धि का प्रतीक है। एक खुशहाल जीवन की आशा में, शादी के दिन होने वाली बारिश को अच्छे भाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

नई शुरुआत—बारिश के बाद हर चीज साफ हो जाती है और हर चीज तरोताजा एवं नई नजर आती है। जो लोग शादी करने करने जा रहे हैं वो भी नए सपने बुनते हुये एक साथ एक नई जिंदगी बसर करने जा रहे हैं। बारिश एक नई शुरुआत की सूचक है। परिवार के बढने का संकेत—इसके साथ ही बारिश परिवार के बढने का संकेत है। पानी से चीजें उगती और बढती हैं। लोगों को उम्मीद होती है शादी के बाद उन्हें बच्चों की प्राप्ति होगी। इसलिए कुछ संस्कृतियों में माना जाता है बारिश नवयुगल के बच्चे पैदा होने और परिवार बढने का संकेत है, इसलिए यह एक प्रकार का आशीर्वाद है।

भौतिक संपत्ति—चीजों में वृद्धि होने तात्पर्य भौतिक धन—धान्य से है इसलिए यह प्रचुर मात्रा में संसाधनों, उत्पादकता, और एक अच्छी फसल आदि का प्रतीक है। एकता—शादी के दिन बारिश होने को एकता का सूचक भी मान सकते हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि शादी वाले आपस में गठजोड़ करते हैं यानि कि "गाँव बांधते हैं।"

भारतीय महिलाएं क्यूं लेती हैं अपने सिर पर घूंघट

हमारे भारतीय समाज में महिलाओं को हमेशा समाजिक परंपराओं को निभाने और मानते हुए देखा गया है, जैसे कि वे हमेशा ही पारंपरिक कपडे, और गहने, पहनती हैं, माथे पर बिंदी लगाती हैं और सर पर घूंघट लेती हैं। भारत में महिलाओं द्वारा सिर को ढकने की प्रथा ने हमेशा ही हमारे अंदर जिज्ञासा बढाई है, खासतौर पर उन लोगों के लिये जो भारतीय संस्कृति से बिल्कुल अलग हैं। हिंदू परंपराओं के पीछे छुपे विज्ञान को समझना है जरूरी सिर पर घूंघट डालना अपने से बड़ों के सम्मान के रूप में देखा गया है, इसलिए महिलाएं अपनों से बड़ों के सामने अक्सर घूंघट करती हैं। शहरों में यह कुछ कम देखने को मिलता है मगर गांवों में आज भी महिलाएं अपने सर, चेहरा और गर्दन को पुरुषों से ढांक के रखती हैं।

भारतीय महिलाएं घूंघट क्यों लेती हैं। क्या कहता है हिंदू ग्रंथ: आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि हिन्दू धर्म ग्रंथों में महिलाओं को पर्दे में रहने का कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि पूजा के समय भी सर पर घूंघट रखना जरूरी नहीं है। भारतीय महिलाएं क्यूं पहनती हैं नोज रिंग सुरक्षा के कारण: कुछ धर्मों में पर्दा रखना इसलिए जरूरी है, क्योंकि यह माना जाता है कि अगर महिलाएं खुद को पर्दे में रखेंगी तो वे अन्य पुरुषों से सुरक्षित रहेंगी। महिलाएं केवल अपने पति या पिता के सामने बेपर्दा हो सकती हैं। मुस्लिम का आक्रमण: महिलाओं को पर्दे में रखने का रिवाज मुस्लिम शासन के बाद से हुआ है। भारत में राजपूत शासन के दौरान महिलाओं को

आक्रमणकारियों के बुरे इरादों से बचाने के लिए उन्हें पर्दा में रखा जाता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं चित्तौड़ की रानी पद्मिनीजिनकी खूबसूरती को देख कर अल उद दीन खिलजी ने उन्हें पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर था। लेकिन रानी पद्मिनी ने जौहर का प्रदर्शन किया और दुश्मन के चंगुल से बचने के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया। तब से भारत में महिलाओं को पर्दे में रखने का रिवाज शुरू हो गया। घूंघट का अस्तित्व



हम क्यूं चढाते हैं सूर्य देवता को जल

हमारे माता—पिता और दादा—दादी हमें बचपन से सिखाते आये हैं की सुबह जल्दी उठो और सूर्य को जल चढाओ ऐसे समाज में जहाँ हम संस्कारों, विश्वासों और मान्यताओं को मानते हैं वहाँ या जानना जरूरी है कि सूर्य को जल चढाना वाकई में लाभप्रद है या एक झूठी मान्यता है। अनेकों शोधकर्ताओं ने लोटे से सूर्य को जल चढाने के वैज्ञानिक कारण बताये हैं। जब हम दोनों हाथ सूर्य की ओर ऊपर करके लोटे से जल प्रवाहित करते हैं तो लोटे से बहुत हल्की धार नीचे आती है और हम सूर्य की तेज किरणों के कारण उसकी तरफ नहीं देख सकते हैं। जब कि हमारे पूर्वज प्रातः काल की बेला में जब सूर्य उदय होता है तो बडे किनारों वाले बर्तन से सूर्य को जल चढाते थे कुछ धर्मों में क्यूं वर्जित है प्याज, लहसुन और मदिरा का सेवन जब वे सूर्य की ओर जल चढाते थे तो गिरते हुए पानी में आँखों के सामने सूर्य की परछाई दिखाई देती थी इससे हमारे पूर्वज और साधु संत सूर्य के दर्शन कर लिया करते थे।

इससे सूर्य की किरणें बहते पाने से फिल्टर होकर आती थी जो कि ना केवल आखों के लिए अच्छा है बल्कि इससे हमारे पूर्वजों को शरीर और आत्मा में नई ऊर्जा का संचार होता था। वैज्ञानिकों के अनुसार सुबह के समय सूर्य की किरणें मनुष्य के लिए लाभकारी हैं क्यूं कि हमारा शरीर ऊर्जा से बना है और एक प्रकाश पुंज की भांति है। मनुष्य का शरीर हवा (वायु), पानी (जल), धरती (पृथ्वी), अग्नि (एनर्जी) और अंतरिक्ष (आकाश) से मिलकर बना है इसलिए शरीर की विभारियों का ईलाज इन पांच तत्वों में निहित है और उगते हुए सूर्य की किरणें इनमें से एक हैं। सूर्य की किरणों में बहुत सी विभारियों का ईलाज संभव है जैसे कि हार्ट की बीमारियां, आँख, पीलिया, कुष्ठ और कमजोर दिमाग से सम्बंधित बीमारियां हिंदू क्यूं नहीं खाते गोमांस ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्य हमें जगता है। इसी के कारण हम एक्टिव रहते हैं और काम कर पाते हैं। सारा चराचर जगत सूर्य पर निर्भर है। सूर्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कमजोरियों को हटाकर हमें स्वस्थता और लम्बी उम्र प्रदान करता है। सूर्य के सात रंग स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि व्यक्ति सुबह नहा—धोकर पूजा अर्चना करे और इसके बाद सन—बाथ ले यानि सूर्य की किरणों को अपने ऊपर आने दे तो इससे शरीर को रोगमुक्त रखा जा सकता है और बुद्धिमता भी बढाई जा सकती है।



दूसरी तरफ कुछ लोगों की मान्यताएं हैं कि सूर्य प्यासा नहीं है और क्या इस तरह हमारा जल सूर्य तक पहुँचता है। इसको सिद्ध करने के लिए एक संत ने गंगा के किनारे पानी को निकलने के लिए 2-3 फीट का एक रास्ता बना दिया जब लोगों ने पुछा कि वह गंगा के पवित्र पानी को खराब क्यों कर रहा है तो संत ने कहा कि उसने पानी को अपने खेतों की ओर मोड़ा है। अन्य संतों ने क्रोधित होकर कहा कि पानी ऐसे उसके खेतों तक कैसे जा सकता है तो संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि तो क्या तुम्हारे द्वारा सूर्य को चढाया हुआ जल क्या उस तक पहुँचता है। फिर भी 'अर्घ्य' के बारे में हम कौनसी मान्यता को मानें और दो दार्शनिकों में मतभेद बरकरार रहता है।

क्या है यमराज द्वारा बताये मृत्यु रहस्य

हम सभी जानते हैं कि हम अमर नहीं हैं और एक दिन हमें मरना है। काल की घडी में धवी राज या भिखारी का एक ही स्थान है। जब भी मृत्यु का विषय आता है, चर्चा काफ़ी रोचक हो जाती है क्योंकि सभी मृत्यु के बारे में और जानना चाहते हैं। लोग मृत्यु के बारे में सब कुछ जानने के लिये जिज्ञासु हो जाते हैं। जो लोग ऐसी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं वो सही जगह पर आये हैं क्योंकि बोल्लेस्की मृत्यु के देवता यमराज द्वारा मृत्यु के बारे में बताये गये कुछ छिपे रहस्यों को उजागर कर रहा है। प्रचीन धर्मग्रन्थों के अनुसार मृत्यु और आत्मा के रहस्यों के बारे में यमराज और नचिकेत नामक बालक के बीच चर्चा हुई थी। क्या है हिन्दु धर्म में मृत्यु का संकेत यहाँ पर कुछ रहस्यों को उजागर किया जा रहा है जिन्हें मृत्यु के देवता यमराज द्वारा नचिकेत को बताया गया था।



नचिकेत के वरदान—जब नचिकेत यमराज से मिलने गये तो उन्होंने ने तीन वरदान माँगे। पहले वरदान में पिता के प्रेम की कामना, दूसरे में अग्नि विद्या का ज्ञान और तीसरे में मृत्यु और आत्मा का ज्ञान माँगा। यमराज अन्तिम वरदान को नहीं पूरा करना चाहते थे लेकिन बालक ने हट किया। इसलिये यमराज मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके रहस्योद्घाटन के लिये तैयार हो गये।

रहस्योद्घाटन—धर्मग्रन्थों के अनुसार यमराज ने बताया कि ओउम (ओंकार) परमात्मा का स्वरूप है। उन्होंने यह भी बताया कि मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा का वास होता है। **आत्मा**—यमराज ने कहा कि आत्मा मनुष्य की मृत्यु के बाद भी नहीं मरती। संक्षेप में, शरीर का आत्मा के विनाश से कोई सम्बन्ध नहीं है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती न मरती है।

ब्रह्मरूप—मृत्यु के बाद मनुष्य जन्म—मृत्यु के चक्र को पूरा करता है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य जन्म—मृत्यु के चक्र अर्थात ब्रह्म रूप से मुक्त हो जाता है। **ईश्वरीय शक्ति**—यमराज ने कहा कि जो लोग ईश्वर में आस्था नहीं रखते और नास्तिक होते हैं वे मृत्यु के बाद भी शान्ति की तलाश में रहते हैं। उनकी आत्मायें भी शान्ति की तलाश करती हैं।



दुनिया में हर काम में लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि उनमें समझ नहीं रहती है बल्कि वो उस तक अक्षम्य होते जाते हैं, उस काम को करने में, उस काम को उस तरीके से समझने में, उसकी आधुनिकता को समझने में। अगर आप भी किसी काम को बखूबी करने के बाद अचानक से उसमें गिरावट महसूस करते हैं तो समझें कि शायद आपको उसमें भी कुछ नयापन लाने की जरूरत है या फिर आपको उस काम सेवानिवृत्ति ले लेनी चाहिए। दुनिया में जो भी निर्मित है, जिसका भी निर्माण किया गया है, सभी में अध्यात्म का सार होता है, सभी के जीवन का एक चक्र होता है। एक सम्पूर्ण जीवन के बाद उसे खींचना या जबरन इस्तेमाल करना या चलाना सिर्फ मनुष्य की जिद होती है।

तो आपको अपने जीवन की दिशा और ऊर्जा को सही करने का मौका मिलता है, बस उस बिंदु को जिसने समझा वह सच्चा व्यक्ति है। सफलता और सच्चाई में रती भर भी अंतर नहीं है दोनों ही पूरक हैं। लडकी—हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि जिस दिन उसका जन्म होता है उसी दिन से उसके मरने की स्पैड क्लॉक चलने लगती है, कोई भी नश्वर नहीं होता है। अगर आप एक अच्छे विश्लेषणकर्ता हैं तो आपको कई बार इसका आभास भी हो जाएगा। अगर आप इन बातों को मजाक मानते हुए शरीर को ही सबकुछ मान लेते हैं तो स्वयं को मूर्ख बनाते हैं। पत्थर—बढती उम्र सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपका शरीर कांपने लगा है, इसे आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं।

आपने इतनी उम्र बिताई, हजारों यादें लोगों को दी और उन्हें प्रेरणा दी, सहारा दिया, प्यार दिया, अच्छे पल दिए, इसलिए जब आखिरी सांसे लें तो मुस्कराएं और सोचे कि जो भी वक्त बितया वो बेहतरीन था। इस सोच की कमी हमारी गलती नहीं है बल्कि हमारी पारंपरिक सोच का नतीजा है, हमारा हर तरीके से न सोचने का परिणाम है। कई बार तो जिंदगी के बुरे अनुभव भी लोग एक—दूसरे के साथ साझा नहीं करते हैं उन्हे लगता है कि इससे बदनामी होगा, उन्हे शायद यह नहीं मालूम होता है कि न अनुभवों से किसी को राह मिल सकती है, किसी को सबक मिल सकता है। पर नहीं हम कभी ऐसा नहीं करते हैं। हमें अमरता चाहिए, हम डरते हैं कि हम नश्वर है, पर सच ये है कि दुनिया में हर क्षण, हर दिल, हर वस्तु, प्राणी सब कुछ नश्वर है। नाश सभी का होता है पर अनुभव उसे जीवित रखता है। जीवन में मृत्यु में फर्क नहीं होता है, फर्क सोच में होता है।

मां पार्वती के जल से गणेश का अभिषेक

बुधवार को अच्छी बारिश की कामना को लेकर हजारों महिला—पुरुष पार्वती नदी का जल लेकर चिंतामन गणेश मंदिर पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान का जल से अभिषेक किया। उसके बाद विधि विधान से पूजा—अर्चना कर अच्छी बारिश, सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना की। ज्ञात हो कि हर वर्ष अषाढ के माह में ग्राम पार्वती लोग पार्वती नदी में से जल भरकर व झंडा लेकर हजारों की तादात में पैदल जत्थे के रूप में सीहोर स्थित चिंतामन गणेश मंदिर पहुंचते हैं। इस दौरान रास्ते में पडने वाले दर्जनों गांव के लोग उनका स्वागत कर उनके साथ जत्थे में शामिल हो जाते हैं। यह जत्था पार्वती से शुरू होता है, जिसमें पिंपलिया नगर, बाबडिया, खजूरी, मूंडला, कराडिया, बकल, जगनीखेडी, बिजोरा, बिजोरी, नयापुरा, पीलीखेडी, कोडिया, महोडिया सहित दर्जनों ग्राम के लोग शामिल होते हुए चिंतामन गणेश मंदिर पहुंचते हैं। जहां पूजा अर्चना के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। यह परम्परा कई वर्षों से चली आ रही है, जिसमें सभी ग्रामीण बडे सद्भाव और सोहार्द के साथ हिस्सा लेते हैं, जिसमें बच्चे—बूढे, महिला—पुरुष सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं।

इस पर्वत पर गिरा था देवी सती का सिर

चंबा—मसूरी मोटर मार्ग पर तीन हजार मीटर की ऊंचाई पर सुरकुट पर्वत पर सिद्धपीठ सुरकंडा मंदिर स्थित है। मान्यता है कि देवी सती का सिर इस पर्वत पर गिरा था। गंगा दशहरे के मौके पर यहां मेला लगता है, जबकि हर साल नवरात्रि में मंदिर में विशेष पूजा—अर्चना की जाती है। जब राजा दक्ष ने हरिद्वार कनखल में यज्ञ किया तो उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। शिव के मना करने पर भी देवी सती यज्ञ में शामिल होने चली गईं। वहां भगवान शिव का अपमान होने पर वे यज्ञ में कूद गईं। भगवान शिव को जब यह पता चला तो वह क्रोधित होकर यज्ञ स्थल पर पहुंचे। यहां सती की देह को त्रिशूल में लटकाकर सृष्टि में विचरण करने लगे। इस दौरान सुरकुट पर्वत पर सती का सिर गिरा जिस कारण इसका नाम सुरकंडा पडा। तभी से यह स्थान सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। सिद्धपीठ सुरकंडा मंदिर इकलौता सिद्धपीठ है, जहां गंगा दशहरे के मौके पर मेला लगता है और हर साल नवरात्रि में मंदिर में विशेष पूजा—अर्चना की जाती है। खास बात यह है कि मंदिर में प्रसाद के रूप में रौंसली (थुनेर) के पत्ते दिए जाते हैं। दूर—दूर से लोग इस सिद्धपीठ के दर्शनों के लिए यहां आते हैं।



बुद्ध संसार के हर प्राणी से इतना प्रेम करते थे

भगवान बुद्ध एक बार उपदेश देने एक गांव में पहुंचे। वहां उनके पडाव का अंतिम दिन था। तब वह उस गांव के एक व्यक्ति के यहां पहुंचे। वो गरीब था। उसके पास भगवान बुद्ध के आतिथ्य के लिए कुछ भी न था। तब उसने घर के बाहर देखा। जहां उसकी नजर बरसात में भीगी लकड़ियों पर पडी, जिन पर कुकुरमुत्ता(मशरूम) लगे हुए थे। उसने उन्हें तोड़ा और बडे ही प्रेमपूर्वक उनकी सब्जी बनाई। लेकिन उस गरीब को पता नहीं था की मशरूम काफ़ी कडवे जहर के समान थे। वह बुद्ध से पूछता कि कैसा है भोजन और बुद्ध कहते बहुत ही स्वादिष्ट। मशरूम जहरीले थे। जिसके कारण उसका जहर बुद्ध के शरीर में फैल गया। यह देख उस व्यक्ति ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने बुद्ध से कहा, कि जब आपको मशरूम कडवे लगे तब आपने उस व्यक्ति से क्यों नहीं कहा।



ममता बनर्जी जनादेश का अपमान कर रहीं : धर्मद प्रधान

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मद प्रधान ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को बंदूक की नोक पर रखा जा रहा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जनता के जनादेश की सच्ची भावना की अवहेलना करने का आरोप लगाया। प्रधान ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जनादेश को जनता की आवाज की बजाय अस्वीकृत के लिए खुले सुझावों की तरह माना जा रहा है, जिससे यह सवाल उठता है कि सत्ता को जिम्मेदारी के रूप में लिया जा रहा है या अधिकार के रूप में। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र को बंदूक की नोक पर रखा जा रहा है, और चुनावी नतीजों को नकारना इस वास्तविकता को स्पष्ट करता है। जनादेश को जनता की आवाज की बजाय ऐसे सुझावों की तरह माना जा रहा है जिन्हें खारिज किया जा सकता है। ममता बनर्जी द्वारा जनादेश की भावना को स्वीकार न करना एक गंभीर प्रश्न उठाता है: क्या सत्ता को एक जिम्मेदारी के रूप में लिया जा रहा है या केवल एक अधिकार के रूप में?

ममता के इस्तीफा न देने पर दिलीप घोष का तीखा जवाब

कोलकाता। भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने बुधवार को ममता बनर्जी को फटकार लगाई। ममता ने राज्य विधानसभा चुनावों में टीएमसी की करारी हार के बाद भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद से हटने से इनकार कर दिया था। टीएमसी प्रमुख पर उनके 15 साल के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार और हिंसा को लेकर हमला बोलते हुए घोष ने कहा कि यह गद्दी तो बस दो दिन की है और एक दिन तो इंसान को यह दुनिया भी छोड़नी पड़ती है। गौरतलब है कि बंगाल चुनाव में भाजपा को जबरदस्त बढ़त मिली है और वह राज्य में अगली सरकार बनाने की तैयारी में है। भगवा पार्टी ने 207 सीटें हासिल कीं, जबकि टीएमसी को सिर्फ 80 सीटों तक ही सीमित कर दिया। उन्होंने कहा, एक दिन आपको यह दुनिया छोड़नी ही है, इसलिए यह गद्दी तो बस दो दिन की है। उन्हें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि यह उनकी पुरैनी संपत्ति है। लोगों ने उन्हें 15 साल दिए, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार और हिंसा के अलावा कुछ नहीं किया।

पश्चिम बंगाल में सुवेदु अधिकारी की ताजपोशी तय!

कोलकाता। सुवेदु के मुताबिक, 2026 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद सुवेदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की करारी हार के बाद भी प्रबल दावेदार के रूप में उभरे हैं। भारतीय जनता पार्टी 8 मई को कोलकाता में एक महत्वपूर्ण विधानसभा बैठक आयोजित करने जा रही है, जहां सरकार गठन और नेतृत्व पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में अधिकारी के भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने की उम्मीद है, जो सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले एक महत्वपूर्ण कदम है। सुवेदु के अनुसार, भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख समिक भट्टाचार्य उनका नाम प्रस्तावित करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा औपचारिक रूप से इस निर्णय की घोषणा किए जाने की संभावना है। इस चुनाव में अधिकारी का उदय सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार तब सुविध्या बेटों जब उन्होंने नंदीग्राम चुनाव में ममता बनर्जी को हराया।

असम के सीएम हिमंता ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिससे नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया। विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन का औपचारिक मार्ग प्रशस्त करते हुए मुख्यमंत्री ने राजभवन में राज्यपाल आचार्य से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री सरमा के साथ रानोज पेगू और मानव डेका सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि मंत्रिपरिषद का इस्तीफा भी सौंप दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि राज्यपाल ने मौजूदा सरकार को नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक प्रशासन के रूप में काम जारी रखने का निर्देश दिया है। अगले मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, इस सवाल पर मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि यह फैसला भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा।

केरल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सरपेंस बरकरार

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चैत्रिथला बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे। विधानसभा चुनावों में मिली शानदार जीत के बाद पार्टी को अभी केरल के अगले मुख्यमंत्री का चयन करना बाकी है। के.सी. वेणुगोपाल और रमेश चैत्रिथला, विपक्ष के नेता वीडी सतीशान के साथ केरल के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं। इससे पहले चैत्रिथला ने कहा था कि इन सभी मुद्दों पर अंतिम फैसला पार्टी ही लेगी। केरल में हमें शानदार जीत मिली है, अब बाकी मामलों पर कांग्रेस हाई कमांड फैसला करेगी। कांग्रेस पार्टी में कई नेता हैं, सभी कांग्रेस नेता उसे स्वीकार करेंगे। केरल में कांग्रेस ने सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जहां पार्टी के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने विधानसभा चुनावों में भारी जीत दर्ज करते हुए 140 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटें जीती हैं।

तमिलनाडु में डीएमके को दोहरा झटका: पहले चुनाव हारे, अब कांग्रेस ने तोड़ा नाता

कांग्रेस ने टीवीके को दिया सशर्त समर्थन

नई दिल्ली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके को नई सरकार बनाने के लिए कांग्रेस की तरफ से समर्थन दे दिया गया है। कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने बताया था कि टीवीके प्रमुख ने उनसे समर्थन मांगा था। इसीलिए वो सशर्त समर्थन देने के लिए तैयार हैं। कुछ देर बाद कांग्रेस ने इस बात का आधिकारिक एलान भी कर दिया। स्टालिन की द्रमुक समर्थन वाली बात से चुरी तरह से भड़क गई है। द्रमुक ने अपने सबसे पुराने राष्ट्रीय सहयोगी कांग्रेस के इस अचानक पाला बदलने वाले कदम को पीठ में छुड़ा घोंपना बताया। बता दें, इस चुनाव में द्रमुक को करारी हार का सामना करना पड़ा है और अब उसके सबसे पुराने साथी ने भी उसका साथ छोड़ दिया है, जिससे राजनीतिक माहौल बेहद गर्म हो गया है।



द्रमुक के प्रवक्ता सरवन अन्नादुरई ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी ने टीवीके के साथ गठबंधन करने और उन्हें अपना समर्थन देने का जो फैसला किया है, वह एक बहुत बड़ा धोखा है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ द्रमुक की ही नहीं, बल्कि पूरे तमिलनाडु की जनता की पीठ में भी छुरा घोंपा है। अन्नादुरई ने अपनी गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि कांग्रेस ने तमिलनाडु की जनता द्वारा दिए गए जनादेश का भी घोर अपमान किया है। यह सब इतनी जल्दी हुआ है कि चुनाव प्रक्रिया अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी और कांग्रेस ने टीवीके से हाथ मिला लिया।

द्रमुक प्रवक्ता ने कांग्रेस को इस जल्दबाजी पर तंज कसते हुए कहा कि जीत के प्रमाण पत्र पर चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर की स्पष्टी अभी सूखी भी नहीं थी कि कांग्रेस ने अपना नया गठबंधन तय कर लिया। अन्नादुरई ने कांग्रेस को उसका पुराना इतिहास याद दिलाते

प्रतिबद्धता दिखानी होगी। काँग्रेस के गौरवशाली दिनों की वापसी... टीवीके और कांग्रेस के इस गठबंधन को राज्य में महान नेता पेरुथलैवर कामराज के गौरवशाली दिनों को वापस लाने की दिशा में मिलकर काम करना होगा।

तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों (बहुमत) की जरूरत होती है। चुनाव में टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं और अब 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने भी उन्हें अपना समर्थन दे दिया है। इन दोनों पार्टियों को मिलाने पर कुल आंकड़ा 113 (108+5) पहुंचता है। इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ कांग्रेस के समर्थन भर से टीवीके पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकती है। बहुमत के जादुई आंकड़े (118) तक पहुंचने के लिए टीवीके को अभी भी कम से कम पांच और विधायकों की जरूरत है।

बहुमत साबित करने और सरकार बनाने के लिए टीवीके को अब अन्य दलों की मदद लेनी होगी। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा तेज है कि अन्नादुरई टीवीके को सरकार बनाने के लिए बिना शर्त समर्थन दे सकती है। इसके अलावा द्रमुक नेता कनिमोश्री ने भी यह दावा किया है कि अन्नादुरई के 21 विधायक टूटकर सीधे टीवीके में शामिल हो सकते हैं। अगर अन्नादुरई का समर्थन मिलता है या कुछ अन्य छोटे दल और निर्दलीय विधायक टीवीके के पाले में आते हैं, तो विजय आसानी से बहुमत का यह आंकड़ा पार कर लेंगे और राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अन्नादुरई ने टीवीके प्रमुख विजय पर भी सीधा निशाना साधा। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद विजय ने अपने निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के मतदाताओं को ठीक से धन्यवाद कम नहीं दिया। द्रमुक नेता ने दावा किया कि विजय ने जनता से पहले प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया।

इंडिया गठबंधन में तीन तलाक! भाजपा बोली -

कांग्रेस ने डीएमके को इस्तेमाल करके फेंका

नई दिल्ली। कांग्रेस की तीखी आलोचना करते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बुधवार को पार्टी पर अपने सहयोगियों को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि वे अपने गठबंधन सहयोगियों का उपयोग करके छोड़ देते हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने आरजेडी, शिवसेना, एनसीपी और अब डीएमके जैसी पार्टियों का उपयोग करके उन्हें त्याग दिया है, और भारतीय गठबंधन को एक स्पष्ट लक्ष्य और दूरदृष्टि से रहित बताया। मीडिया से बात करते हुए पूनावाला ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों के मामले में कांग्रेस सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है। वे गठबंधन सहयोगियों, क्षेत्रीय पार्टियों का उपयोग करके उन्हें त्याग देते हैं। हमने देखा है कि उन्होंने आरजेडी का उपयोग किया और उसे त्याग दिया। उन्होंने शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के शरद पवार गुट का उपयोग किया और उन्हें त्याग दिया। अब उन्होंने डीएमके का उपयोग किया, सीटें हासिल कीं, और उन्हें त्याग रहे हैं। इसलिए भारतीय गठबंधन एक लक्ष्य और दूरदृष्टि वाला गठबंधन नहीं है।



कांग्रेस को सिर्फ सत्ता की लालसा है। उन्होंने डीएमके का इस्तेमाल किया और फेंक दिया, और कांग्रेस का व्यवहार हमेशा ऐसा ही होता है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, यह एक परजीवी की तरह है। यह सिर्फ वोट बैंक के लिए क्षेत्रीय पार्टी का इस्तेमाल करती है, और एक बार वोट बैंक मिल जाने पर, यह आगे बढ़ जाती है।

इस बीच, भारत गठबंधन में दरार खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस और डीएमके के बीच सबसे लंबे समय से चले आ रहे गठबंधनों में से एक अब टूटने की कगार पर है, क्योंकि कांग्रेस ने तमिलनाडु में विजय के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने की मंजूरी दे दी है। द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम (डीएमके) के प्रवक्ता सरवन अन्नादुरई ने बुधवार को कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए इस फैसले को दूरदर्शिता की कमी वाला बताया और उन पर भारत के सहयोगी दलों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस का यह रुख बहुत ही अदूरदर्शी और संकीर्ण है, जिसका उन्हें पछतावा होगा। 2029 के बड़े चुनाव आ रहे हैं, जिनमें हमें पूरा भरोसा है कि हम भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे। लेकिन अब कांग्रेस के इस फैसले से वे एक बहुत ही अस्थिर सहयोगी बन गए हैं। पूरे देश में यही धारणा बन गई है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुवेदु के अनुसार, विजय के नेतृत्व वाली पार्टी को 2026 के विधानसभा चुनावों में बहुमत के लिए 102 सीटें कम मिलने के बाद, कांग्रेस ने सर्वसम्मति से राज्य में सरकार बनाने के लिए तमिलनाडु के वीडी कजगम (टीवीके) का समर्थन करने का फैसला किया है।

विजय की सरकार के लिए एआईएडीएमके का बाहर से समर्थन! पलानीस्वामी पर भारी दबाव

एआईएडीएमके सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए विजय के नेतृत्व वाली टीवीके को बाहरी समर्थन देने का फैसला किया है। इस फैसले में एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता सीवी शनमुगम और एसपी वेलुमुत्तम को अहम भूमिका बताई जा रही है। यह फैसला एआईएडीएमके के भीतर बढ़ते आंतरिक मतभेद की खबरों के बाद आया है, जिसमें पार्टी के 47 विधायकों में से बड़ी संख्या में विधायकों ने पार्टी नेतृत्व से टीवीके का समर्थन करने का आग्रह किया था। इस विवाद के कारण एआईएडीएमके विधायकों को एक महत्वपूर्ण बैठक भी स्थगित कर दी गई। सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि एडप्पाडी पलानीस्वामी को जल्द से जल्द अपना रुख स्पष्ट करने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा 30 से अधिक विधायक पार्टी से अलग होकर विजय को अपना समर्थन दे सकते हैं। विधानसभा चुनावों में टीवीके के शानदार प्रदर्शन के बाद, जहां पार्टी ने कुल 234 सीटों में से 108 सीटें हासिल कीं।



स्टेल प्रमुख समाचार

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ प्लेऑफ का रास्ता

मुम्बई। कप्तान ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सत्र अच्छा नहीं रहा है और वह अब तक इस टूर्नामेंट में मिली सातवां हार के साथ ही तकरीबन प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गयी है हालांकि आधिकारिक तौर पर देखें तो तब भी सुपर जायंट्स की संभावनाएं बनी हुई हैं पर उसे बचे हुए सभी पांच मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे। कप्तान ऋषभ ने भी स्वीकार किया कि उनकी टीम को अब टॉप-4 में पहुंचने के लिए काफी किस्मत की जरूरत होगी। वह गलत नहीं हैं, क्योंकि 9 मैचों में 2 जीत और 7 हार के साथ ही सुपरजायंट्स को अब प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए अन्य टीमों के परिणामों के उसके अनुसार आने पर निर्भर रहना होगा।

प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को बनाये रखने के लिए, लखनऊ को अब अपने बचे हुए सभी मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे। उन्हें 7 मई को रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु (आरसीबी), 10 और 15 मई को दो बार चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके), 19 मई को राजस्थान रॉयल्स (आर) और 23 मई को पंजाब किंग्स (पंजाब किंग्स) का सामना करना है। इन सभी पांच मैचों में जीत से उन्हें 10 और अंक मिलेंगे, जिससे वे सत्र के अंत में 14 अंक हासिल कर सकते हैं

हालांकि, केवल अपनी जीत पर्याप्त नहीं होगी। लखनऊ की टीम को अपनी जीत के साथ यह भी उम्मीद करनी होगी कि पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स जैसी मजबूत टीमों अपने ज्यादातर मैच जीतें। इससे ये टीमों 16 या उससे अधिक अंक हासिल कर शीर्ष-3 प्लेऑफ स्थानों को पकड़ कर सकेंगी, जिससे चौथे स्थान के लिए मुकाबला खुला रहे। इसके अलावा उसे ये भी उम्मीद करनी होगी कि रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु,

सेंसेक्स 941 अंक चढ़ निफ्टी 24,300 के पार

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में कारोबार के दूसरे हिस्से में तेज उछाल देखा गया, क्योंकि ब्रेट क्रूड (कच्चे तेल) की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष खत्म होने की उम्मीदों के चलते बेंचमार्क इंडेक्स संसेक्स 941 अंक उछल गया, जबकि निफ्टी-50 24,300 अंक के पार निकल गया। 30 शेयरों वाला बीएसई संसेक्स 77,424.36 अंक पर खुला। दिन के कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 78,022.78 के हाई और 76,773.25 के लो रेंज में ट्रेड किया। अंत में संसेक्स 940.73 अंक यानी 1.22% उछलकर 77,958.52 पर बंद हुआ। इसी तरह, 50 शेयरों वाला निफ्टी-50 24,171.00 अंक पर खुला। दिन के कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 24,356.50 के हाई और 23,997.90 के लो रेंज में ट्रेड किया। अंत में निफ्टी-50 298.15 अंक यानी 1.24% चढ़कर 24,330.95 पर बंद हुआ।

अप्रैल में सर्विसेज पीएमआई 5 महीने के टॉप पर

नई दिल्ली। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ को लेकर बड़ा बूस्ट देखने को मिला है। बुधवार को जारी एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई के अनुसार, मजबूत घरेलू मांग, ई-कॉमर्स गतिविधियों में तेजी और नए ऑर्डर्स में सुधार के चलते अप्रैल में भारत की सर्विसेज सेक्टर की गतिविधियां पांच महीनों टॉप पर पहुंच गईं। सीजनली एडजस्टेड इंडेक्स मार्च के 57.5 के 14 महीने के निचले स्तर से बढ़कर अप्रैल में 58.8 पर पहुंच गया। सर्वे के मुताबिक, हर दमदार ग्रोथ मजबूत घरेलू मांग, नए ऑर्डर्स, प्रतिस्पर्धी कीमतों और ई-कॉमर्स गतिविधियों में तेजी के चलते हुई, जबकि पश्चिम एशिया युद्ध के चलते निर्यात ग्रोथ कमजोर रही। एचएसबीसी की मुख्य भारत अर्थशास्त्री प्रांजल भंडारी ने कहा, भारत का सर्विसेज पीएमआई अप्रैल में बढ़कर पांच महीने के टॉप 58.8 पर पहुंच गया।

गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर संयंत्रों की स्थापना की मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,936 करोड़ रुपये से अधिक के कुल निवेश के साथ दो अन्य सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूरी दी गई है। इनमें देश की पहली वाणिज्यिक मिनी/माइक्रो-एलईडी डिस्प्ले इकाई (गैलियम नाइट्राइड प्रौद्योगिकी पर आधारित) और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई शामिल है। दक्षिण कोरिया की क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड गुजरात के धोलेरा में कंपाउंड सेमीकंडक्टर निर्माण और एटीएमपी (असेंबली, परीक्षण, मार्किंग एवं पैकेजिंग) की एकीकृत इकाई स्थापित करेगी। इस संयंत्र में मिनी/माइक्रो-एलईडी डिस्प्ले मांड्यूल का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने इसे एक नई प्रौद्योगिकी बताते हुए कहा कि यह देश के लिए दीर्घकालिक रूप से लाभकारी होगी।

114 डॉलर से लुढ़ककर 107 डॉलर पर आया कच्चा तेल

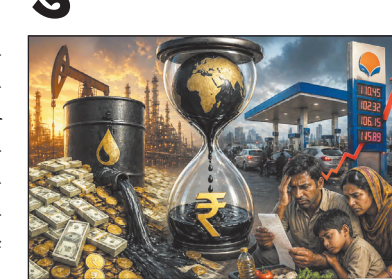
नई दिल्ली। बुधवार, 6 मई 2026 की सुबह रॉयल मार्केट से राहत की खबर आई है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के संकेतों में नरमी आने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय समयानुसार आज सुबह ब्रेट क्रूड लगभग 107 डॉलर प्रति बैरल के पास आ गया, जो कि मंगलवार तक 114 डॉलर के करीब पहुंच गया था। तेल की कीमतों में इस गिरावट की मुख्य वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। ट्रंप ने 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' को फिलहाल रोकने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिकी नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाल रही थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर बड़ी प्रगति हुई है।

तेल कंपनियों का रिकॉर्ड मुनाफा और उपभोक्ताओं पर बढ़ता बोझ

कातिलाल मांडोट

भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान देश की विप्लव तेल कंपनियों ने जिस तरह से मुनाफा कमाया है, उसने आम जनता, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के बीच नई बहस को जन्म दे दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इन कंपनियों ने योजना औसतन 116 करोड़ रुपये का लाभ कमाया, जो पूरे वर्ष में करीब 1.37 लाख करोड़ रुपये के आसपास बैठता है। यह आंकड़ा न केवल चौंकाने वाला है बल्कि यह भी संकेत देता है कि बाजार की जटिल परिस्थितियों के बावजूद कंपनियों की कमाई लगातार मजबूत बनी हुई है। पिछले तीन वर्षों से तेल कंपनियों का मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव,

भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद कंपनियों ने अपने मार्जिन को बनाए रखा है। खास बात यह है कि जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो कंपनियां कीमतें बढ़ाने की बात करती हैं, लेकिन जब कीमतें घटती हैं, तो उपभोक्ताओं को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। 2022-23 में रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद कच्चे तेल की कीमतें 125 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं। उस समय भी अधिकांश तेल कंपनियों ने भारी मुनाफा कमाया था। इसके बाद 2023-24 और 2024-25 में कीमतों में कुछ गिरावट आई, लेकिन कंपनियों के लाभ में कोई खास कमी नहीं आई। 2025-26 में भी यही ट्रेंड जारी रहा। केन्य एज रेटिंग के अनुसार, तीसरी तिमाही में रिफाइनिंग मार्जिन प्रति बैरल लगभग 13 डॉलर तक पहुंच गया था, जो भारतीय मुद्रा



में करीब 1,235 रुपये होता है। इसका सीधा असर कंपनियों की कमाई पर पड़ा। अगर पेट्रोल और डीजल के स्तर पर देखा जाए, तो कंपनियों को प्रति लीटर 7 से 6 रुपये तक का लाभ मिल रहा था। इससे पहले 2024-25 में यह मार्जिन 12 से 14 रुपये प्रति लीटर तक था। यह साफ दिखाता है कि कंपनियों ने लागत और बिक्री मूल्य के बीच एक ऐसा संतुलन बनाया है, जिससे उनका मुनाफा लगातार बढ़ता रहा। हालांकि, दूसरी ओर उपभोक्ताओं की

स्थिति उतनी मजबूत नहीं रही। आम जनता को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अपेक्षित राहत नहीं मिल पाई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटने के बावजूद घरेलू स्तर पर कीमतों में सीमित कटौती ही देखने को मिली। इससे यह सवाल उठता है कि क्या तेल कंपनियों का मुनाफा उपभोक्ताओं की कीमत पर बढ़ रहा है। 2026 की शुरुआत में ईरान से जुड़े भू-राजनीतिक तनाव और युद्ध की स्थिति ने एक बार फिर तेल बाजार को प्रभावित किया। 26 फरवरी 2026 से शुरू हुए इस संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई और यह 125 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। हालांकि बाद में कीमतें घटकर 116 डॉलर तक आ गईं। इस दौरान तेल कंपनियों ने दावा किया कि उन्हें पेट्रोल पर प्रति लीटर 14 रुपये और डीजल पर 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। लेकिन यह दावा उस

समय सवालों के घेरे में आ गया जब उनके पिछले मुनाफे के आंकड़े सामने आए। विशेषज्ञों का मानना है कि तेल कंपनियों अपने नुकसान और मुनाफे को संतुलित तरीके से प्रस्तुत करती हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो नुकसान का हवाला दिया जाता है और जब कीमतें घटती हैं तो मुनाफे की बात कम ही सामने आती है। यह रणनीति बाजार और उपभोक्ताओं दोनों को प्रभावित करती है। सरकार को भूमिका भी इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने 27 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज इयूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी, जिससे आम जनता को कुछ राहत मिली। हालांकि इससे सरकार को हर महीने करीब 12,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है। इस घाटे की भरपाई के लिए सरकार ने डीजल के निर्यात पर टैक्स बढ़ा दिया, जिससे अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है।

सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित इस जन चौपाल में मंत्री ने न केवल ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं,

अबूझामाड़ के कुतुल पहुंचे मंत्री कश्यप

रायपुर। बस्तर के सुदूर वनांचल में विकास की नई किरण पहुंची है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप आज पहली बार नारायणपुर जिले के दुर्गम क्षेत्र कुतुल पहुंचे। सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित इस जन चौपाल में मंत्री ने न केवल ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, बल्कि प्रशासन को सीधे जनता के द्वार पर खड़ा कर दिया।

पेड़ की छांव में गुंजी विकास की बात: ओरछा विकासखंड के कुतुल में पेड़ों की शीतल छांव में आयोजित इस चौपाल में भारी जनसंख्या उमड़। ग्रामीणों ने अपने बीच सीधे प्रदेश के मंत्री को पाकर अपनी मांगें प्रमुखता से रखीं। ग्रामीणों ने मोबाइल नेटवर्क, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता और युवाओं के लिए खेल मैदान की आवश्यकता पर



जोर दिया। मंत्री श्री कश्यप ने इन समस्याओं के शीघ्र निराकरण का भरोसा दिलाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी आवेदन लंबित न रहे। मौके पर ही समस्याओं का निपटारा: जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त आवेदनों पर प्रशासन की तत्परता देखने को मिली। कुल 201 आवेदनों में से

162 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। शेष आवेदनों के लिए संबंधित विभागों को निश्चित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करने को कहा गया है। जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव: अधिकारियों ने बताया कि कुतुल जैसे सुदूर गांव में शासन की योजनाओं की पहुंच उत्साहजनक है। महतारी वंदन

योजना (114 हितग्राही), नौनी सुरक्षा (11) और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना (14) से ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 179 परिवारों के सिर पर पक्की छत का सपना साकार हो रहा है।

मंत्री श्री कश्यप ने चौपाल के दौरान सामाजिक सरोकारों से

जुड़ते हुए गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की और बच्चों का अन्नप्राशन कराया। उन्होंने विशेष रूप से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और आंगनबाड़ी व स्कूलों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। कुतुल का यह दौरा प्रशासन और जनता के बीच की दूरी पाटने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास है।

इस अवसर पर मंत्री ने हितग्राहियों को राशन कार्ड, सुपोषण किट और आवास प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, कलेक्टर नम्रता जैन, एसपी रॉबिन गुरिया और जिला पंचायत सीईओ सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

भाजपा में संगठनात्मक गतिविधियां तेज 20 में से 14 मंडलों की बैठकें सम्पन्न

■ जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को दिया मार्गदर्शन



रायपुर। पार्टी नेतृत्व के निर्देशानुसार रायपुर शहर जिला में संगठनात्मक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी तारतम्य में मंडल बैठकों का सिलसिला निरंतर जारी है। अब तक शहर जिला के 20 मंडलों में से 14 मंडलों की बैठकें सम्पन्न हो चुकी हैं, जिनमें मंडल कार्यकारिणी के साथ वरिष्ठ नेताओं की भी सक्रिय सहभागिता रही। शेष मंडलों की बैठकें 7 मई को आयोजित की जाएंगी।

इन बैठकों में बूथ कमेटियों एवं शक्ति केंद्रों की रचना, साथ ही मन की बात कार्यक्रम को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। स्मरण रहे कि मई माह के अंतिम रविवार, 31 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से संवाद करेंगे।

उन्होंने मन की बात कार्यक्रम की वास्तविक ताकत बूथ स्तर पर होती है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ एवं शक्ति केंद्र को मजबूत बनाने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को प्रत्येक बूथ पर सामूहिक रूप से सुनने और अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। रमेश सिंह ठाकुर ने टिफिन बैठक की सगहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन कार्यक्रमों के बीच आत्मियता और संवाद को बढ़ाते हैं, जो संगठन की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है।

आईपीएल मैच की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक



रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने 10 एवं 13 मई को राजधानी के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होने वाले आईपीएल मैच की तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के साथ बैठक ली। कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण आयोजन है। पाकिंग की समुचित व्यवस्था की जाए तथा सामानों की ओवरसैरिंग न हो। पुलिस प्रशासन से समन्वय कर सुरक्षा एवं ट्रैफिक के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मैदान के एंटी प्लांट पर वालेंटियर की तैनाती करें तथा वाईफाई एवं इंटरनेट की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए ताकि दर्शकों को प्रवेश में किसी प्रकार की समस्या न हो। उन्होंने कहा कि मैदान में खिलाड़ियों के साथ दर्शकों के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित रहें। प्रशासन की एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। आपदा के समय क्या किया जाए, इसकी कार्ययोजना पहले से तैयार रखें। डॉ. सिंह ने कहा कि आग से बचाव के लिए आवश्यक

उपकरणों का अनिवार्य रूप से इंतजाम किया जाए तथा जिला सेनानी से समन्वय स्थापित कर उपकरणों का पूर्ण परीक्षण कर लिया जाए। सभी गेट पर आयोजन समिति के वालेंटियर रहें और दर्शकों की सुविधाजनक आवाजाही सुनिश्चित करें। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए स्टेडियम और स्टेडियम परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए गए। क्रिकेट संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस बार केवल ऑनलाइन माध्यम से टिकट की बिक्री की जा रही है। बैठक में निगम आयुक्ता विश्वदीप, रायपुर ग्रामीण को प्रभारी एसपी मनीषा ठाकुर, एडीएम उमाशंकर बंदे, एसपी विवेक शुक्ला, छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के सीईओ हेरी गोंडालपे, बीसीसीआई के प्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर पहुंची मुंबई इंडियंस की टीम



■ हार्दिक-रोहित को देखने विमानतल पर उमड़े फैंस

रायपुर। मुंबई इंडियंस की टीम 10 मई को होने वाले बड़े मुकाबले से पहले रायपुर पहुंच चुकी है। टीम के आते ही एयरपोर्ट पर फैंस की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग अपने-अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते नजर आए और पूरे माहौल में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। टीम के साथ कप्तान हार्दिक पांड्या और

दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा समेत सभी खिलाड़ी पहुंचे। एयरपोर्ट पर फैंस ने नारे लगाकर उनका स्वागत किया, जिससे माहौल पूरी तरह क्रिकेटमय हो गया।

मैच के टिकट ऑनलाइन उपलब्ध हैं और उनकी कीमत 2,500 से शुरू होकर 8,000 या उससे अधिक तक जा रही है। 10 मई के मुकाबले के टिकट तेजी से बिक रहे हैं, जिससे मैच को लेकर फैंस की दीवानगी साफ नजर आ रही है। राज्य सरकार ने भी इस आयोजन को खस बनाने के लिए पहल की है। 10वीं और 12वीं बोर्ड में टॉप करने वाले छात्रों को 10 मई का मैच मुफ्त में देखने का मौका दिया जाएगा, जिससे युवाओं में भी उत्साह बढ़ गया है।

आगामी खरीफ सीजन की रणनीति पर मंथन



रायपुर। कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार की अध्यक्षता में आज सरगुजा जिला कलेक्टर सभाकक्ष में सरगुजा संभाग स्तरीय एपीसी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में रबी वर्ष 2025-26 की प्रगति की समीक्षा करते हुए आगामी खरीफ सीजन वर्ष 2026 के लिए कार्ययोजना तय की गई।

कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचे और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उद्यानिकी क्षेत्र में भी योजनाबद्ध प्रयास बढ़ाने के निर्देश दिए। पशुपालन में चारा विकास और नस्ल सुधार को महत्वपूर्ण बताते हुए इस दिशा में ठोस कार्ययोजना बनाने पर बल दिया गया। बैठक में नाशपाती, लीची और कटहल जैसे स्थानीय फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने और उनकी गुणवत्ता सुधार कर बाजार से जोड़ने की रणनीति पर भी चर्चा हुई।

सभी जिलों को प्रमाणित बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। उर्वरक वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए आगामी खरीफ 2026 से लागू होने वाली नई ई-उर्वरक वितरण प्रणाली पर विस्तृत चर्चा हुई।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

गोली मारकर हत्या गैंगवार, अपराध रुक नहीं रहा : बैज

रायपुर। राजधानी सहित प्रदेश में बढ़ती अपराध की घटनाएं सब बर्दाश्त के बाहर होते जा रही हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राजधानी में कल गोली मारकर हत्या कर दी गयी, एक महिला गंभीर रूप से घायल है। दो दिन पहले चाकूबाजी से एक युवक की हत्या कर दी गयी। एक नाबालिक गंभीर रूप से घायल हो गया। राजधानी में रोज अपराधिक घटनाएं बढ़ते जा रही, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अंबेडकर अस्पताल के पास खुलेआम गैंगवार होता है, छोटे अपराधी चाकू, तलवार, फरसा लहराते हैं, आने जाने वाले राहगीर में डर पैदा होता है। चाकूबाजी लूट तो आम हो गयी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने कानून व्यवस्था सुधारने के नाम पर राजधानी में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू किया लेकिन कमिश्नरी प्रणाली भी अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही है। राजधानी ही नहीं पूरा प्रदेश बढ़ते अपराधों के कारण परेशान है। कवर्धा में हत्या हो गयी, पद्मश्री फुलबासन बाई का अपहरण करने का प्रयास किया जाता है, सरगुजा में विवाह से लौट रही दो किशोरियों से गैंगरेप हो जाता है। मुख्यमंत्री की क्या यही सुशासन है? इसी का ल्यूहार मना रहे है आप?



नाम पर राजधानी में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू किया लेकिन कमिश्नरी प्रणाली भी अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही है। राजधानी ही नहीं पूरा प्रदेश बढ़ते अपराधों के कारण परेशान है। कवर्धा में हत्या हो गयी, पद्मश्री फुलबासन बाई का अपहरण करने का प्रयास किया जाता है, सरगुजा में विवाह से लौट रही दो किशोरियों से गैंगरेप हो जाता है। मुख्यमंत्री की क्या यही सुशासन है? इसी का ल्यूहार मना रहे है आप?

प्रदेश में अवैध शराब धड़ले से बिक रही: शुक्ला

रायपुर। प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री दयालदास बघेल ने भरे मंच से राज्य में अवैध शराब बिक्री की हकीकत को स्वीकार किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब से राज्य में भाजपा की सरकार बनी है, प्रदेश अवैध शराब का गढ़ बन चुका है। प्रदेश के गांव-गांव, गली, कूचे में खुलेआम अवैध शराब बिक रही है। सरकारी अमला इस अवैध शराब बिक्री को खुला संरक्षण देता है। मंत्री दयालदास बघेल स्वयं बता रहे कि किसी आदमी के 1 बोतल शराब मिल जाये तो उसके खिलाफ पुलिस कार्यवाही कर देती है, शराब भट्टी से पेट्टी-पेट्टी शराब लेकर खुलेआम बेची जा रही कार्यवाही नहीं होती है। मंत्री बघेल ने स्वीकार किया कि राज्य में अवैध शराब की बिक्री के लिए पुलिस विभाग और आबकारी विभाग दोनों जिम्मेदार हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात को शुरू से उठाती रही कि राज्य में अवैध शराब की बिक्री हो रही, तब सरकार इस मामले में चुप थी। अब सरकार के मंत्री स्वयं सुशासन तिहार में मंच से अवैध शराब की बिक्री की बात कबूल रहे हैं। विपक्ष में रहकर शराबबंदी के लिए कसमें खाने वाली, शराबबंदी की दुहाई देने वाली भाजपा की सरकार ने राज्य में शराब की दुकानों की संख्या दगुनी कर दिया है।



विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब से राज्य में भाजपा की सरकार बनी है, प्रदेश अवैध शराब का गढ़ बन चुका है। प्रदेश के गांव-गांव, गली, कूचे में खुलेआम अवैध शराब बिक रही है। सरकारी अमला इस अवैध शराब बिक्री को खुला संरक्षण देता है। मंत्री दयालदास बघेल स्वयं बता रहे कि किसी आदमी के 1 बोतल शराब मिल जाये तो उसके खिलाफ पुलिस कार्यवाही कर देती है, शराब भट्टी से पेट्टी-पेट्टी शराब लेकर खुलेआम बेची जा रही कार्यवाही नहीं होती है। मंत्री बघेल ने स्वीकार किया कि राज्य में अवैध शराब की बिक्री के लिए पुलिस विभाग और आबकारी विभाग दोनों जिम्मेदार हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात को शुरू से उठाती रही कि राज्य में अवैध शराब की बिक्री हो रही, तब सरकार इस मामले में चुप थी। अब सरकार के मंत्री स्वयं सुशासन तिहार में मंच से अवैध शराब की बिक्री की बात कबूल रहे हैं। विपक्ष में रहकर शराबबंदी के लिए कसमें खाने वाली, शराबबंदी की दुहाई देने वाली भाजपा की सरकार ने राज्य में शराब की दुकानों की संख्या दगुनी कर दिया है।

कानून व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर नहीं: ठाकुर

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार ने ढाई साल में पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति नहीं कर पायी। इससे सम्पन्न में आता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार कितना गंभीर है, यही कारण है प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर है, पूर्णकालिक डीजीपी नहीं होना सरकार की अनिर्णय की स्थिति को स्पष्ट कर रहा है, सरकार आखिर कौन चला रहा है? सरकार के फैसले दिली से होंगे तो इसलिए ये स्थिति निर्मित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य में स्थायी डीजीपी का न होना प्रशासनिक विफलता और सरकार की कमजोर इच्छाशक्ति को दर्शाता है। पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, ये सरकार की अनिर्णय स्थिति को दर्शाता है। कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी जिस पद पर टिकी होती है, वही पद लंबे समय से अस्थायी व्यवस्था के भरोसे चल रहा है। इससे न केवल पुलिस विभाग का मनोबल गिरता है, बल्कि अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक समन्वय पर भी गंभीर असर पड़ता है। सरकार राजनीतिक हितों और अंदरूनी खींचतान के चलते योग्य अधिकारी की नियुक्ति नहीं कर पा रही है।



कानून व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर नहीं: ठाकुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार ने ढाई साल में पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति नहीं कर पायी। इससे सम्पन्न में आता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार कितना गंभीर है, यही कारण है प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर है, पूर्णकालिक डीजीपी नहीं होना सरकार की अनिर्णय की स्थिति को स्पष्ट कर रहा है, सरकार आखिर कौन चला रहा है? सरकार के फैसले दिली से होंगे तो इसलिए ये स्थिति निर्मित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य में स्थायी डीजीपी का न होना प्रशासनिक विफलता और सरकार की कमजोर इच्छाशक्ति को दर्शाता है। पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, ये सरकार की अनिर्णय स्थिति को दर्शाता है। कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी जिस पद पर टिकी होती है, वही पद लंबे समय से अस्थायी व्यवस्था के भरोसे चल रहा है। इससे न केवल पुलिस विभाग का मनोबल गिरता है, बल्कि अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक समन्वय पर भी गंभीर असर पड़ता है। सरकार राजनीतिक हितों और अंदरूनी खींचतान के चलते योग्य अधिकारी की नियुक्ति नहीं कर पा रही है।

आर. वेंकटेश्वरलु ने संभाला एनएचएआई रायपुर के क्षेत्रीय अधिकारी का पदभार

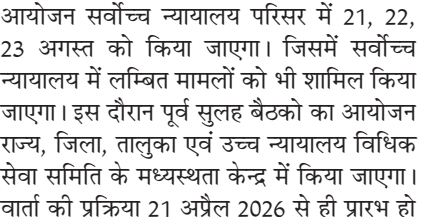
रायपुर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) में आर. वेंकटेश्वरलु ने नए क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में आज पदभार ग्रहण किया। उन्होंने विधिवत रूप से कार्यभार संभालते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया। इससे पूर्व वे ओडिशा के कोरापुट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में पदस्थ थे। वहीं निवर्तमान क्षेत्रीय अधिकारी श्री प्रदीप कुमार लाल अपने स्थानांतरण के बाद आज कार्यमुक्त हुए। वे अब क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर (ओडिशा) में क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे।



रायपुर के नए क्षेत्रीय अधिकारी का पदभार ग्रहण करने के बाद श्री आर. वेंकटेश्वरलु ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एनएचएआई द्वारा संचालित परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य तथा समयबद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को टीम भावना के साथ कार्य करते हुए राष्ट्रहित में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने को कहा।

9 मई को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन

रायपुर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आम जनता तक पहुंचने तथा आपसी सहभागिता एवं सहमति से विवादों के समाधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाधान समारोह विशेष लोक अदालत 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह आगामी 09 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत आरंभ होकर 21, 22 एवं 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों का निराकरण सम्पन्न होगा। विशेष लोक अदालत का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय परिसर में 21, 22, 23 अगस्त को किया जाएगा। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को भी शामिल किया जाएगा। इस दौरान पूर्व सुलह बैठकों का आयोजन राज्य, जिला, तालुका एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के मध्यस्थता केन्द्र में किया जाएगा। वार्ता की प्रक्रिया 21 अप्रैल 2026 से ही प्रारंभ हो चुकी है। इस समाधान शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का आपसी सहमति एवं सुलह के माध्यम से निष्पादन करना है। अधिवक्ता वादीगणों एवं संबंधित सभी पक्षों से अपील की गई है कि, सक्रिय रूप से भाग ले एवं आपसी सहमति से समाधान की दिशा में प्रयास करें। सुलह बैठक में पक्षकार शारीरिक एवं अभासी माध्यम से भी सम्मिलित हो सकते हैं, इस बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थता एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी सहयोग प्रदान करेंगे।



रायपुर। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर-20 में आयोजित प्रेरणा समर-केएम में मोटिवेशनल स्पीकर इन्जीनियर बी. एन. राव ने बच्चों के मन में गणित के प्रति रुचि पैदा करते हुए बहुत ही सरलता के साथ उनकी कठिनाइयों का समाधान भी किया। इन्जीनियर बी. एन. राव ने कहा कि गणित जैसा आसान कोई दूसरा विषय नहीं है। गणित का भय अपने मन से निकाल दें। गणित के अधिकांश आविष्कार हमारे देश में हुए किन्तु यहाँ पर गणित को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना कि अमेरिका आदि देशों में दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इतिहास को आप रट सकते हो लेकिन गणित को नहीं रट सकते। उसे समझकर हल करना पड़ता है। गणित एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें पूरे नम्बर प्राप्त किए जा सकते हैं। हमारे देश में कई महान गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। इस देश के महान गणितज्ञों ने वर्षों पहले धरती से सूर्य के बीच की दूरी को गणना करके बतला दिया था। यहाँके बच्चे अन्य देशों की अपेक्षा गणित में होशियार होते हैं। अमेरिका में यह हालत है कि वहाँ के बच्चे बिना केलकुलेटर के छोटी मोटी गणना भी नहीं कर सकते हैं।

कृषि शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग की संभावनाएं तलाशेंगे

अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल होंगे उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल

रायपुर। भारत एवं उज्बेकिस्तान के मध्य कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए उज्बेकिस्तान का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज रायपुर पहुंचा। इस इस प्रतिनिधि मंडल में बुखारा स्टेट यूनिवर्सिटी से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उप-कुलपति प्रो. अब्दुर जोरायेव तुरोबोविच तथा समरकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ़ वेटेरनरी मेडिसीन लाइवस्टॉक एवं बायोटेक्नोलॉजी से अनुसंधान एवं नवाचार के उप-कुलपति प्रो. तयलाकोव तोलिब इसाकुलोविच सहित अन्य वरिष्ठ शिक्षाविद् एवं वैज्ञानिक शामिल हैं। यह प्रतिनिधि



मंडल कुल 7 मई 2026 को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भारत एवं उज्बेकिस्तान के मध्य द्विपक्षीय शैक्षणिक, अनुसंधान एवं तकनीकी सहयोग सुदृढ़ीकरण विषय पर आयोजित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी शामिल होगा। इस संगोष्ठी का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य शैक्षणिक संबंधों को और सुदृढ़ करना तथा कृषि मूदा

विज्ञान, फसल मूल्य श्रृंखला, जैव प्रौद्योगिकी प्रोसेसिंग एवं तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों में नए सहयोगात्मक अवसरों का मार्ग प्रशस्त करना है। उजबेक प्रतिनिधि मंडल 7 और 8 मई को छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर रहेगा। इस दौरान यह अध्ययन दल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर

माह उज्बेकिस्तान के तरमेज़, डेनाऊ, ताशकंद, बुखारा एवं समरकंद स्थित प्रमुख विश्वविद्यालयों, कृषि संस्थानों एवं अनुसंधान केंद्रों का दौरा किया था। इस शैक्षणिक यात्रा ने संयुक्त अनुसंधान, कृषि नवाचार, जैव प्रौद्योगिकी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों, स्टार्टअप तथा उद्यमिता विकास जैसे विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की मजबूत आधारशिला रखी। यह यात्रा भारत एवं उज्बेकिस्तान के मध्य शैक्षणिक एवं तकनीकी सहयोग को संस्थागत रूप प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुई।

ब्रह्माकुमारीज समर कैम्प

रायपुर। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर-20 में आयोजित प्रेरणा समर-केएम में मोटिवेशनल स्पीकर इन्जीनियर बी. एन. राव ने बच्चों के मन में गणित के प्रति रुचि पैदा करते हुए बहुत ही सरलता के साथ उनकी कठिनाइयों का समाधान भी किया। इन्जीनियर बी. एन. राव ने कहा कि गणित जैसा आसान कोई दूसरा विषय नहीं है। गणित का भय अपने मन से निकाल दें। गणित के अधिकांश आविष्कार हमारे देश में हुए किन्तु यहाँ पर गणित को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना कि अमेरिका आदि देशों में दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इतिहास को आप रट सकते हो लेकिन गणित को नहीं रट सकते। उसे समझकर हल करना पड़ता है। गणित एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें पूरे नम्बर प्राप्त किए जा सकते हैं। हमारे देश में कई महान गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। इस देश के महान गणितज्ञों ने वर्षों पहले धरती से सूर्य के बीच की दूरी को गणना करके बतला दिया था। यहाँके बच्चे अन्य देशों की अपेक्षा गणित में होशियार होते हैं। अमेरिका में यह हालत है कि वहाँ के बच्चे बिना केलकुलेटर के छोटी मोटी गणना भी नहीं कर सकते हैं।



जाना है जितना कि अमेरिका आदि देशों में दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इतिहास को आप रट सकते हो लेकिन गणित को नहीं रट सकते। उसे समझकर हल करना पड़ता है। गणित एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें पूरे नम्बर प्राप्त किए जा सकते हैं। हमारे देश में कई महान गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। इस देश के महान गणितज्ञों ने वर्षों पहले धरती से सूर्य के बीच की दूरी को गणना करके बतला दिया था। यहाँके बच्चे अन्य देशों की अपेक्षा गणित में होशियार होते हैं। अमेरिका में यह हालत है कि वहाँ के बच्चे बिना केलकुलेटर के छोटी मोटी गणना भी नहीं कर सकते हैं।